कमल संदेश

लाल किले में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन

वर्ष-14, अंक-03 01-15 फरवरी, 2019 (पाक्षिक) ₹20

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही तृणमूल कांग्रेस

वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन | दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि पर विशेष | गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी

मालदा (पश्चिम बंगाल) में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

अहमदाबाद (गुजरात) में उत्तरायण पर्व मनाते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

सिद्धगंगा मठ के संत श्री शिवकुमार स्वामी के ब्रह्मलीन होने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। श्री शाह स्वामीजी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, जब वे जीवित थे।

नई दिल्ली में 'भीम महासंगम विजय संकल्प' रैली के अवसर पर समरसता खिचड़ी बनाते भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, श्री विजय गोयल, डॉ. हर्षवर्धन और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 बंगाल को कंगाल करने का काम किया तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार ने : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 जनवरी को मालदा (पश्चिम बंगाल) के शाहपुर बाईपास खेल मैदान में एक विशाल एवं भव्य जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से लोकतंत्र का...

वैचारिकी
सही शब्द : सही अर्थ-1 12

श्रद्धांजलि
विचारक देवेन्द्र स्वरूप नहीं रहे 15

लेख
राजनीतिक स्थिरता, निर्णायक नेतृत्व और एक स्पष्ट जनादेश का सीधा संबंध है विकास के साथ... 16

प्रगति से प्रभावित हुए प्रवासी 18

अन्य
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के... 10

भाजयुमो का विजय लक्ष्य 2019 अभियान 17

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से एक करोड़ से अधिक लोगों ... 19

दीनदयाल उपाध्याय : कुशल संगठक व विचारक राजनेता 20

85,429 करोड़ का बजट पेश, 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम खोला जाएगा 21

लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग का अनुपम संगम है भारत: नरेन्द्र मोदी 24

प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा में 1500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं...25

कांग्रेस ने कभी नहीं किया अम्बेडकर का सम्मान : थावरचंद गहलोत 28

राष्ट्र निर्माण में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका है: नरेन्द्र मोदी 29

गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी 30

प्रधानमंत्री का दादरा और नगर हवेली दौरा 31

किसानों की आमदनी दोगुनी करने में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का महत्वपूर्ण योगदान : राधा मोहन सिंह 32

अप्रैल 2014 से 1.37 करोड़ ग्रामीण आवासों का हुआ निर्माण 33

09 मनरेगा को अब तक का सर्वाधिक 61,084 करोड़ रुपया दिया गया

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के लिए 6,084 करोड़...

11 प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जनवरी को...

22 केंद्र सरकार ने प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी को वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में...

26 लाल किले में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन

स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जनवरी को...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

बीते चार-साढ़े चार वर्षों में जिस तरह भाजपा ने केंद्र और राज्यों में सरकारें चलाई हैं, उसने जनमानस में यह स्थापित कर दिया है कि देश को अगर नई ऊंचाई पर कोई राजनीतिक दल ले जा सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है।

@AmitShah

2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के विकास, सुरक्षा और गौरव का चुनाव है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि 2019 का चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतते हैं तो एक लंबे समय तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का शासन रहेगा।

@Ramlal

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रारम्भ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत' के तहत अभी तक 8.4 लाख मरीजों का निःशुल्क इलाज हुआ। अब ना होगा कोई लाचार, बीमारियों का होगा मुफ्त इलाज, भारत को 'आयुष्मान भारत' में बदल रही है मोदी सरकार।

facebook

अंत्योदय का संकल्प पूरा कर रही मोदी सरकार, 2018-19 में आयोजित आदि महोत्सवों से 14,000 हजार जनजातीय परिवारों और 40,000 जनजातीय कारीगरों को मिले आजीविका के साधन।

— कैलाश विजयवर्गीय

भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नारा दिया है #BetiBachaoBetiPadhao इसी मूल मंत्र पर चलते हुए झारखण्ड सरकार ने बेटियों के लिए यह योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे आपके खाते में भेजा जाएगा। बेटियों को समान अधिकार मिले, उनके सपनों को साकार करने में सरकार हर कदम पर उनके साथ है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के माध्यम से बेटियों की पढ़ाई-लिखाई और विदाई तक सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी।

—रघुबर दास

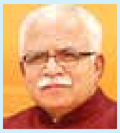

पलवल में बनने जा रहे देश के पहले श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मिलेंगे रोजगार के अवसर।

— मनोहर लाल

अंततः पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की जीत होगी

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर निरंतर भयंकर हमले हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रदेश में भाजपा को मिल रहे व्यापक समर्थन को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। यह इतना नीचे तक चली गई है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर को भी जनसभा के लिए उतरने नहीं देना चाहती। और तो और, भाजपा के सभी कार्यक्रमों में तरह-तरह के अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। रथ यात्रा रोकी जा रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनसभा के लिए लगाये गये तोरण द्वार, बैनर, पोस्टर एवं अन्य सजावट को भी तृणमूल के गुंडे बख्शने से गुरेज नहीं कर रहे। यह सब तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगातार जनता का विश्वास खोते जाने की खिसियाहट ही है। हमारे देश में लोकतंत्र जन-जन की भागीदारी से मजबूत हुआ है और जनता के मन में लोकतांत्रिक परंपरा एवं मूल्यों के प्रति भारी आदर है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी हथकंडों का जवाब देने मालदा की जनसभा में जनता ने जबरदस्त भागीदारी कर इसे सफल बनाया। यह तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है।

यह अत्यंत दूर्भाग्यपूर्ण है कि जो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वाममोर्चे की सरकार के लोकतंत्र विरोधी क्रियाकलापों का विरोध कर सत्ता में आयी थी, आज उन्हीं सब हथकंडों को अपनाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। अब अपने गुंडातंत्र से सत्ता पर कब्जा जमाना और सरकारी मशीनरी पर कब्जा कर उसका दुरुपयोग कर अपना राजनीतिक हित साधने के जुगत में लगी हुई है। स्थिति इतनी खराब है कि हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग में इसने वाम मोर्चो को भी अब पीछे छोड़ दिया है। पंचायत चुनावों में जिस प्रकार की हिंसा देखी गई, यहां तक कि कई लोगों की जानें तक चली गईं, यह केवल ममता बनर्जी की सत्ता लिप्सा को ही दिखाता है। इतना ही नहीं, इस हिंसा की राजनीति में सौ से अधिक भाजपा कार्यकर्ता अब तक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मतलब गुंडाराज, हिंसा, तोड़-फोड़, भ्रष्टाचार, कुशासन और लोकतंत्र का विरोध है।

श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक अपने जबरदस्त कार्यों से प्रदेश को देश में अग्रणी प्रदेश में ले आये और यही कारण था कि पूरा देश उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। यह उनके कड़े परिश्रम, ईमानदारी एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम था कि देश के कोने-कोने में उनके लिए भारी समर्थन जुटने लगा।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 'परिवर्तन' का नारा देकर सत्ता में आई थी, परंतु इनके शासन में प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसने संस्कृति से लेकर आर्थिक मामलों में देश का नेतृत्व किया, परंतु ममता बनर्जी प्रदेश के इस समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन की बयार बह रही थी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के केंद्र में यह प्रदेश था, परंतु वाममोर्चा एवं ममता बनर्जी की सरकार ने जिस दुरवस्था में प्रदेश को पहुंचा दिया इसे हर कोई समझ सकता है। यह अब एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दुर्गा पूजा विसर्जन तथा सरस्वती पूजा पर रोक लगाने का प्रयास होता है। जो प्रदेश अपने कल-कारखानों एवं व्यापार के लिए जाना जाता था, आज वह सुशासन एवं विकास के मानदंडों में पिछड़ चुका है। यहां बेरोजगारी की समस्या बांग्लादेश से तृणमूल सरकार की राजनीतिक सरपरस्ती में हो रहे घुसपैठ से और भी विकराल रूप ले चुकी है। यह अत्यंत दुःख की बात है कि पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे प्रदेश का उदाहरण है जहां यह देखा जा सकता है कि वोट बैंक की राजनीति किस प्रकार से किसी प्रदेश को बर्बाद कर सकती है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि जो अपने प्रदेश में विकास और सुशासन नहीं दे पाई, आज पूरे देश को नेतृत्व देने का ख्वाब पाल रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है फिर भी हास्यास्पद तरीके से इन्हें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें स्वीकार लिया जाएगा। श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक अपने जबरदस्त कार्यों से प्रदेश को देश में अग्रणी प्रदेश में ले आये और यही कारण था कि पूरा देश उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। यह उनके कड़े परिश्रम, ईमानदारी एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम था कि देश के कोने-कोने में उनके लिए भारी समर्थन जुटने लगा। पर ममता बनर्जी को लगता है कि अपने प्रदेश को बर्बाद कर कुछ ऐसे नेताओं को जुटा कर, जो स्वयं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकती है, तो यह उनकी भयंकर भूल है। पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को जनादेश देने का मन बना चुकी है। श्री अमित शाह की मालदा रैली में आया जबरदस्त जनसैलाब आने वाले दिनों की कहानी बयां कर रहा है। ममता बनर्जी लोकतंत्र विरोधी हथकंडों से भाजपा को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, परंतु जिस प्रकार का जनसमर्थन भाजपा के पक्ष में दिख रहा है इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अंततः पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की ही जीत होगी।■

shivshakti@kamalsandesh.org

बंगाल को कंगाल करने का काम किया तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार ने : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 जनवरी को मालदा (पश्चिम बंगाल) के शाहपुर बाईपास खेल मैदान में एक विशाल एवं भव्य जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से लोकतंत्र का गला घोंटने वाली और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करने वाली तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की मांग की।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2019 का चुनाव देश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के भविष्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। यह चुनाव यह तय करने वाला है कि पश्चिम बंगाल में हत्याएं कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या उखाड़ फेंक दी जायेगी। जो राज्य में लोकतंत्र का गला घोंट रही है, भारतीय जनता पार्टी को यात्रा निकालने नहीं दे रही है, ऐसी तृणमूल सरकार रहेगी या जायेगी। भ्रष्टाचार करने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जायेगी। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कराने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जायेगी। शरणार्थियों को नागरिक न बनाने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जायेगी। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा न करने देने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जायेगी। गौ तस्करी और अफीम का व्यापार करने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या जायेगी। जनता के समवेत स्वर में कहा कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि यह चुनाव पश्चिम बंगाल को तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार के कुशासन से मुक्त कराने का चुनाव है। राज्य में एक बार फिर से लोकतंत्र को स्थापित करने का चुनाव है। 2019 का चुनाव स्वामी विवेकानंद, गुरु रबिन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, बटुकेश्वर दत्त और सूर्यसेन का पश्चिम बंगाल फिर से बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में यह महज दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को समाप्त करने वाली तृणमूल कांग्रेस और राज्य की संस्कृति का वंदन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पहले पश्चिम बंगाल कई क्षेत्रों में अग्रणी हुआ करता था, लेकिन लंबे समय तक कम्युनिस्ट शासन और ममता दीदी के शासन के बाद आज राज्य बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल कभी पूरे देश का 27% औद्योगिक उत्पादन करता था, वह कम होते होते 3.3% पर आ गया है। जो पश्चिम बंगाल कभी 32%

औद्योगिक रोजगार मुहैया कराता था, वह आज 4% पर आ गया है। राज्य का हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जा जाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को कंगाल करने का काम तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार ने किया है। राज्य में लोकतंत्र को समाप्त करने पर उतारू है तृणमूल सरकार।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में चार यात्राओं के माध्यम से राज्य के घर-घर में जाने वाले थे। इससे ममता दीदी को डर लग गया। उन्हें लगा कि यदि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकली तो तृणमूल सरकार की अंतिम यात्रा निकल जायेगी। अतः भाजपा को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। कोई बात नहीं ममता दीदी, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पसीना बहायेंगे लेकिन अबकी बार हम पश्चिम बंगाल से तृणमूल सरकार को हटा कर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लिए जो कमल खिला है, उसे ममता दीदी नहीं मिटा सकती। पश्चिम बंगाल की जनता यह तय करके बैठी है कि फिर से श्री नरेन्द्र भाई मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे।

राज्य का हर पांचवां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जा जाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को कंगाल करने का काम तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार ने किया है। राज्य में लोकतंत्र को समाप्त करने पर उतारू है तृणमूल सरकार।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश भर में पंचायत चुनाव होते हैं, शांतिपूर्वक संपन्न होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में 65 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। लगभग 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए। करोड़ों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग तक नहीं कर पाए। हालत तो यह हो गई कि हाई कोर्ट यह आदेश तक देना पड़ा कि उम्मीदवार व्हाट्सअप से भी अपना नॉमिनेशन फ़ाइल कर सकते हैं। राज्य की जनता को ऐसी स्थिति कतई स्वीकार नहीं है।

श्री शाह ने कहा कि दो दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने ब्रिगेड समावेश कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस वालों की काफी आवभगत की थी लेकिन इतना बड़ा समावेश हुआ पर 'भारत माता की जय' के नारे नहीं लगे। वंदे मातरम् नहीं बोला गया। वास्तम में तृणमूल सहित पूरे विपक्ष के सामने अस्तित्व की लड़ाई है, उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं।

कांग्रेस की यूपीए सरकार पर प्रहार जारी रखते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 13वें वित्त आयोग के दौरान देश में सोनिया-मनमोहन-राहुल की कांग्रेस सरकार थी जो अभी तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी है। 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने पश्चिम बंगाल को विकास के लिए महज 1,32,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने राज्य के लिए 3,95,406 करोड़ रुपये आवंटित किये जो कांग्रेस सरकार की तुलना में ढाई गुना है लेकिन यह पैसा पश्चिम बंगाल की जनता तक पहुंचा ही नहीं। वास्तव में आधे पैसे तो तृणमूल कांग्रेस के लोग खा जाते हैं और बाकी आधा घुसपैठियों की भेंट चढ़ जाता है।

श्री शाह ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वस्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप एक बार प्रदेश में कमल खिला दीजिये, एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में कदम न रखने पायेगा। ममता सरकार को घुसपैठिये बड़े अच्छे लगते हैं, ये लोग राज्य की जनता को गुमराह करते हैं। मैं राज्य में रह रहे सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल लेकर आये है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आये हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को भारत की सिटिजनशिप दी जायेगी। ये सभी शरणार्थी ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप संसद में इस विधेयक का समर्थन करेंगी या नहीं। लोक सभा से तो तृणमूल कांग्रेस वाक-आउट कर गई थी, वह राज्य सभा से भी इसे पारित नहीं होने देगी, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तृणमूल सरकार पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा,

सरस्वती पूजा की अनुमति तक नहीं देती। मां सरस्वती हमें जीवन जीने का संस्कार देती है, वाणी और विद्या देती है लेकिन सरस्वती पूजन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। दुर्गा विसर्जन में हमले होते हैं। गौ-तस्करी पर लगाम नहीं लगाया जा रहा, यहां सिंडिकेट टैक्स लगता है। हालत तो यहां तक खराब हो गई है कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री तक को इसके खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। हमें ऐसा प्रदेश नहीं चाहिए, हमें वही गौरवशाली बंगाल चाहिए शांति और समृद्धि का प्रतीक है। आप एक बार पश्चिम बंगाल में कमल खिला दीजिये, आप लोगों को भी सिंडिकेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज प्रदेश के हर गांव में जगाई-मधाई है, इसे प्रदेश की जनता ही रोक सकती है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ही प्रदेश की सत्ता से कम्युनिस्टों को बाहर किया था और फिर से वे ही तृणमूल कांग्रेस को भी राज्य की सत्ता से बाहर करेगी।

श्री शाह ने कहा कि तृणमूल सरकार के संरक्षण में आज पश्चिम बंगाल में हर जगह कारखानों की जगह बम बनाने की फैक्ट्रियां लग रही हैं। कई जगह बम-धमाके हो रहे हैं, गैर-कानूनी आर्म्स फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं। प्रदेश में सारी फैक्ट्रियां बंद है, केवल एक धंधा चालू है, बम और हथियार बनाने का धंधा। यदि पश्चिम बंगाल से ये सब बंद करना है तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी पड़ेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तृणमूल सरकार ने पूरे प्रदेश में प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी जनसभा के लिए हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति तक नहीं दी गई, यात्रा की अनुमति नहीं दी गई, मैं डीएम की स्थिति समझता हूं क्योंकि यदि उन्होंने अनुमति दे दी तो ममता दीदी का कोपभाजन बनना पड़ेगा। वह दिन दूर नहीं है जब आपकी सत्ता का अंत होगा क्योंकि जुल्म तो रावण का भी नहीं टिका था। आप हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं देंगी तो हम हेलीकॉप्टर से ही भाषण करेंगे लेकिन आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप यात्रा निकालने की अनुमति नहीं देंगी तो हम रैली करेंगे लेकिन आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप रैली नहीं करने देंगी तो पैदल मार्च करेंगे, लेकिन आपके खिलाफ लड़ेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है।

तृणमूल सरकार के संरक्षण में आज पश्चिम बंगाल में हर जगह कारखानों की जगह बम बनाने की फैक्ट्रियां लग रही हैं। कई जगह बम-धमाके हो रहे हैं, गैर-कानूनी आर्म्स फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं।

श्री शाह ने कहा कि देश भर में सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी पांचवां वेतन आयोग ही चल रहा है। यदि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग लागू करने का निर्णय कर लिया जाएगा। यहां तक कि राज्य के कर्मचारियों का डीए भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में आधा है। सारा पैसा तो तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। नारदा-सारदा, रोज वैली, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला-न जाने कितने घोटाले किये हैं तृणमूल कांग्रेस ने और तो और, प्रदेश में 5000 करोड़ रुपये की वक्फ बोर्ड की जमीन तक बेच डाली गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मुझे पता है, मेरी जनसभा ख़त्म होते ही ममता दीदी मुझ पर एक केस कर देंगी। मैं जब पिछली बार आया था तो उन्होंने मुझ पर एक केस कर दिया था। ममता दीदी, मैं आयु में आपसे छोटा हूं, एक नहीं, दो केस कीजिएगा लेकिन आप मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती क्योंकि यह पश्चिम बंगाल की जनता के अधिकार का सवाल है। हम पश्चिम बंगाल की जनता के अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारे 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने लोगों के हक़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यदि तृणमूल कांग्रेस समझती है कि वे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करके हमें जनता के लिए लड़ने से रोक लेंगे तो यह उनकी भूल है। आप कमल पर जितना कीचड़ उछालोगी, कमल उतना ही दैदीप्यमान होकर खिलेगा।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के 70 सालों में गरीब-कल्याण के लिए जितने कार्य नहीं हुए, वे सभी कार्य केवल पांच वर्षों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित किये गए, लगभग 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया गया, ढाई करोड़ घर बनाए गए, लगभग 19 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई, अब घरों को रौशन किया जा रहा है। किसानों को उनकी फसल पर डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया गया। देश के गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, लेकिन ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। स्पष्ट है कि गरीब कल्याण में उनकी कोई रुचि नहीं है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तथाकथित महागठबंधन एक ढकोसला, इस गठबंधन का एजेंडा स्पष्ट है। उनका एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हटाना है। हम चाहते हैं गरीबी हटे, वे चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निरक्षरता, बीमारी हटे, वे चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं देश सुरक्षित हो, वे चाहते हैं मोदी हटे। ममता दीदी, मंच पर 5-10 नेताओं को खड़ा कर हाथ हिलाने से नरेन्द्र मोदी को नहीं हटाया जा सकता। देश की सवा सौ करोड़ जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। तथाकथित महागठबंधन के नेता केंद्र में मजबूर और ढीली-ढाली सरकार चाहते हैं, ताकि वे भ्रष्टाचार कर पायें जबकि हम चाहते हैं कि देश में मजबूत सरकार बने जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर सके और मजबूत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। ममता दीदी के ब्रिगेड समावेश मंच पर जो लोग थे, उनमें तो प्रधानमंत्री पद पाने की होड़ लग रखी है, लेकिन एनडीए में एक ही नेतृत्व है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में "न्यू इंडिया" के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को सम्मान देते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम सुभाष, स्वराज और शहीद रखने का निर्णय लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सुभाष बाबू को भुलाने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। ■

मनरेगा को अब तक का सर्वाधिक 61,084 करोड़ रुपया दिया गया

परिसंपत्ति निर्माण, स्थायी आजीविका और गरीबों को रोजगार मिला

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के लिए 6,084 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ कुल आवंटन 2018-19 में 61,084 करोड़ रुपया किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। दरअसल, शासन में सुधार और स्थायी परिसंपत्तियों के माध्यम से चिरस्थायी आजीविका पर जोर देकर मजदूरी, आय और स्थायी परिसंपत्तियों के माध्यम से गरीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया गया।

गौरतलब है कि 'मनरेगा' ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि सामाजिक विषमताओं पर काबू पाने और सतत और दीर्घकालिक विकास के लिए एक आधार तैयार करके पूर्ण रूप से गरीबी को खत्म करता है। 'मनरेगा' ग्रामीण भारत को अधिक उत्पादक, न्यायसंगत और संयुक्त समाज में बदल रहा है। इसने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 235 करोड़ मानव दिवस कार्य प्रदान किया है। इस वर्ष भी यह लगभग समान रहेगा, जिससे चिरस्थायी आजीविका के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के साथ वेतन रोजगार के मामले में यह लगातार चार वर्ष तक उच्च प्रदर्शन कायम रख सकेगा।

पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा में बड़े सुधार किए, हैं जिससे कि इसे गरीबों के लिए चिरस्थायी आजीविका प्रदान करने वाला संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। 2014-15 में केवल 26.85 प्रतिशत मामलों में ही 15 दिनों के अंदर भुगतान किया गया था और उस वर्ष में मुश्किल से 29.44 लाख परिसंपत्तियां ही पूरी की गई थी। इन अंतरों को खत्म करने के लिए राज्यों से साझेदारी करके एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास शुरू किया गया। अब इस निरंतर प्रयास के उल्लेखनीय परिणाम दिखने लगे हैं। 2014-15 और 2017-18/ 2018-19 के दौरान मनरेगा की उपलब्धियां निम्न हैं :

	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2017-18/ वित्तीय वर्ष 2018-19
अब तक उत्पन्न किए गए मानव दिवस	166.21 करोड़	236.41 करोड़
पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या	29.44 लाख	61.9 लाख
व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं	21.4%	66.7%*
धन की कुल उपलब्धता	37,588.03 करोड़ रुपये	68,107.86 करोड़ रुपये
ईएफएमएस के माध्यम से कुल व्यय	77.35%	99.6%*
15 दिनों के भीतर किया गया भुगतान	26.85%	91.82%*

*वित्तीय वर्ष २०18-19 के आंकड़े

'मनरेगा' ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि सामाजिक विषमताओं पर काबू पाने और सतत और दीर्घकालिक विकास के लिए एक आधार तैयार करके पूर्ण रूप से गरीबी को खत्म करता है। 'मनरेगा' ग्रामीण भारत को अधिक उत्पादक, न्यायसंगत और संयुक्त समाज में बदल रहा है। इसने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 235 करोड़ मानव दिवस कार्य प्रदान किया है। इस वर्ष भी यह लगभग समान रहेगा, जिससे चिरस्थायी आजीविका के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के साथ वेतन रोजगार के मामले में यह लगातार चार वर्ष तक उच्च प्रदर्शन कायम रख सकेगा।

सबसे पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता वेतन भुगतान, परिसंपत्ति निर्माण और सामग्रियों के लिए भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता को सुनिश्चित करना था। इस कारण से ही संपत्ति की 100 प्रतिशत जियो-टैगिंग, बैंक खातों को आधार से जोड़ना, सभी प्रकार के वेतनों और सामग्री हेतु भुगतानों के लिए आईटी/डीबीटी स्थानान्तरण और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित कार्य योजना शुरू किए गए। इनका उद्देश्य यह था कि सार्वजनिक डोमेन में काम दिखाई दे और लाभार्थियों को उनके सत्यापित खातों में भुगतान प्राप्त हो सके।

08.01.19 तक जियो मनरेगा को 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है और कार्यक्रम की स्थापना के बाद से 4.08 करोड़ पूर्ण कार्यों में से 3.40 करोड़ पूर्ण कार्य को जियो-टैग किया

जा चुका है और यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

सामाजिक परीक्षण बहुत ही सीमित रूप में था और इसके कार्यान्वयन को बढ़ाकर पूरे देश में फैलाने की आवश्यकता थी। सामाजिक परीक्षण मानकों को विकसित किया जाना था, प्रमाणित सोशल ऑडिटर्स को प्रशिक्षित किया जाना था और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को तेजी से रोल आउट को करने के लिए तैयार किया जाना था।

तकनीकी रूप में जल संरक्षण कार्यों पर पैसा खर्च किया जा रहा था, जबकि कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण अपर्याप्त था और कई बार ऐसी संरचनाएं बनायी गई जिसने अपेक्षित परिणाम नहीं दिया। इस कारण से ही 2015-16 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग के साथ साझेदारी में मिशन जल संरक्षण दिशानिर्देश तैयार किया गया, जिससे भूजल स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो कि तेजी से गिर रहा था।

इस साझेदारी से हमें एक मजबूत तकनीकी नियमावली का निर्माण करने और अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने की अनुमति मिली। बेहतर तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष बेयरफुट तकनीशियनों के कार्यक्रम को शुरू किया गया।

केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 32,977 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,167 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों की बढ़ती आस्था का यह स्पष्ट प्रमाण है। इस कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद से मनरेगा ने 2017-18 में अब तक का सबसे ज्यादा 63,644 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड व्यय हुआ है। इस वर्ष यह व्यय और भी अधिक होने वाला है।

स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 अनुपात अनिवार्य था, जिसके कारण अधिकांशतः रूप से गैर-उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण सिर्फ इसलिए किया जाता था, क्योंकि उस ग्राम पंचायत में अकुशल मजदूरी पर 60 प्रतिशत खर्च किया जा सके। 60:40 अनुपात के सिद्धांत को कमजोर किए बिना, इसे ग्राम पंचायत स्तर के स्थान पर जिला स्तर पर 60:40 अनुपात की अनुमति देकर पहला बड़ा सुधार किया गया। इस सुधार के बावजूद अकुशल मजदूरी पर व्यय,कुल व्यय के अनुपात में 65 प्रतिशत से अधिक है। इसने आय पैदा करने वाली स्थायी परिसंपत्ति पर एक नया जोर पैदा किया है। गौरतलब है कि यह लचीलापन केवल उन परिसंपत्तियों को ग्रहण करने की अनुमति देता है जो उपयोगी हैं। ■

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत कोटा लागू

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 15 जनवरी को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से ही देश के 40,000 कॉलेजों और 900 विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए (ईडब्ल्यूएस) 10 प्रतिशत कोटा लागू किया जाएगा। यह 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसची) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एवं सामान्य सीटों के मौजूदा कोटा से अधिक होगा।

ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने के लिए इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। यूजीसी और एआईसीटीई को यह कोटा लागू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।

एक अन्य प्रमुख घोषणा में श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने राज्य सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे केन्द्र सरकार को 1241.98 रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार 7वें सीपीसी के कार्यान्वयन के कारण बकाया राशि के भुगतान के लिए इन संस्थानों पर (1.1.2016 से 31.3.2019 तक) किए जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च का 50 प्रतिशत वहन भी करेगा। इसका सीधा फायदा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के 29,264 शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके अलावा गैर-सरकारी कॉलेजों/एआईसीटीई के दायरे में आने वाले संस्थाओं के करीब 3.5 लाख शिक्षकों एवं शैक्षणिक कर्मचारियों को भी मिलेगा।

श्री जावड़ेकर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/वित्तपोषित और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से उन्हें उच्च शैक्षणिक मानकों के संकायों को अपनी ओर खीचने तथा बनाए रखने में मदद मिलेगी। ■

प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जनवरी को अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा निर्मित 78 मीटर ऊंचा, 1500 बिस्तरों वाला यह अस्पताल एयर एम्बुलेंस सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न है।

प्रधानमंत्री ने अस्पताल की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस प्रकार का विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, 'अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान अस्पताल देश के अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए आदर्श साबित होगा।'

750 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 17 मंजिलों वाला यह अस्पताल किफायती दामों पर विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करेगा और यह आयुष्मान भारत से सम्बद्ध है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'आयुष्मान भारत के कारण छोटे-छोटे कस्बों तक में नए अस्पतालों की मांग बढ़ रही है। नए अस्पताल तेजी से खुल रहे हैं। डॉक्टरों और अर्द्ध चिकित्साकर्मियों की मांग बढ़ रही है। इस कारण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन हो रहा है।'

श्री मोदी ने कहा कि देश में पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है, जिससे नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। सरकार के लिए गरीबों की चिंता और उन्हें दूर करने की जरूरत सबसे बढ़कर है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'सरकार गरीबों की पक्षधर है और सरकार की गरीबों के प्रति प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत कम मूल्यों पर जेनरिक दवाओं के प्रावधान में प्रतिबिम्बित हुई है। देशभर में लगभग 5000 प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं।'

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सभी के लिए अवसरों की समानता के प्रति संकल्पबद्ध है और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस उद्देश्य के लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा रही है। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लागू करने वाला पहला राज्य बनने के लिए गुजरात सरकार की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में उनकी यह पहली गुजरात यात्रा है। उन्होंने कहा कि जब त्यौहारों का मौसम हों, तो अहमदाबाद की जनता को इतना बड़ा अस्पताल समर्पित करने का इससे बेहतर मौका भला कौन सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत कम नगर निगम ऐसी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के साथ सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के महापौर के रूप में सरदार पटेल की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने शहर में स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ-सफाई के अपने अभियान के साथ एक मिसाल कायम की।

श्री मोदी ने कहा कि वह सबके लिए समान अवसर और सबके विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा- सबका साथ, सबका विकास- भारत की सफलता की राह है। ■

सही शब्द : सही अर्थ-1

दीनदयाल उपाध्याय

समाज, संस्कृति, धर्म और राष्ट्र-ये चारों ही ऐसे शब्द हैं, जिनके साथ जीवन का घनिष्ठ संबंध होते हुए भी उनके बारे में देश में बहुत भ्रम फैला हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जब हम इन शब्दों का कोई पर्याय विदेशी भाषाओं में ढूंढ़ने का प्रयास करते हैं तो वहां उन तथाकथित पर्यायवाची शब्दों के पीछे जो भाव उन भाषाओं में खड़े किए गए हैं, उन्हें अपने देश में भी आरोपित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ये शब्द आज हमारे लिए कष्टप्रद और मतिभ्रम उत्पन्न करने वाले बन गए हैं।

राष्ट्र

सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द की ही आजकल हमारे यहां प्रादेशिक राष्ट्रवाद की कल्पना प्रचलित हो गई है। लोग कहते हैं, जो भी यहां पैदा हो गया है- फिर उसके विचार चाहे जैसे हों-वही इस राष्ट्र का अंग माना जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक सज्जन मुझे संसद में एंग्लो इंडियन सदस्य श्री फ्रैंक एंथोनी द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी विषयक प्रस्ताव की वकालत करते हुए समझाने लगे कि एंग्लो इंडियन भी तो भारत के राष्ट्रीय हैं। अतः जिस भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, उसे क्यों नहीं हमें अपने संविधान में स्थान देना चाहिए? मैंने उनके उत्तर में केवल इतना ही कहा, "राष्ट्रीय हैं या राष्ट्रीय होना चाहिए-इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। यह तो मैं मानता हूं कि जो लोग इस रूप में जन्म लेते हैं, उन्हें राष्ट्रीय बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, किंतु इस बारे में मतभेद हो सकता है कि वे जैसे कुछ आज बने हुए हैं, उसी रूप में पूर्ण राष्ट्रीय हैं अथवा नहीं।'' मैंने उनसे कहा, "आज तो वे अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा मानते हैं और आप कहते हो कि वे राष्ट्रीय हैं, अतः उनकी मांग मान लेनी चाहिए। पर यदि अपने देश में रहनेवाले कुछ रोमन कैथोलिक लोगों ने रोम के पोप को, जिसे वे केवल अपना धर्मगुरु ही नहीं तो सब प्रकार से जीवन का केंद्र मानकर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपुरुषों की श्रेणी में रखने की मांग की तो? और इसी सिद्धांत का सहारा लेकर यदि कुछ लोग अपनी देशबाह्य निष्ठा (Extra-Territorial loyalty) के कारण किसी विदेशी राज्य का हस्तक बनकर हमारे देश में खड़े हो गए तो आप उन्हें क्या कहेंगे?" इस प्रकार राष्ट्रीयता के मूल तत्त्वों के बारे में आज हमारे यहां बहुत भ्रम है, जिनकी स्पष्ट व्याख्या होना राष्ट्र हित में नितांत आवश्यक है।

धर्म

दूसरा शब्द धर्म भी इसी प्रकार भ्रम में फंसा हुआ है। धर्म को उपासना पद्धति के साथ बैठाकर लोग मुसलमान धर्म के समान ही हिंदू धर्म शब्द का भी प्रयोग करते हैं। यह शब्द प्रयोग ठीक नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो अनेक भाव आते हैं, वे केवल पूजा-पद्धति तक ही सीमित नहीं हैं। बहुधा 'धर्म' शब्द का अंग्रेजी पर्याय 'रिलीजन' शब्द को माना जाता है। किंतु इस एक छोटी सी भूल के कारण धर्म शब्द का मूल अभिप्राय लोप हो जाता है और उस पर रिलीजन' शब्द के भाव आरोपित हो जाते हैं। इसके कारण ही आज हमारे राष्ट्र जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं।

समाज

उसी प्रकार यह समाज क्या है? समाज शब्द से क्या अभिप्राय निकलता है? जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, वह कहां से आया, कैसे बना? उसका विकास कैसे और कब प्रारंभ हुआ? इन सब बातों का कोई विचार न कर हम समाज शब्द का अंग्रेज़ी में अनुवाद 'सोसायटी' शब्द से करते हैं और एक क्षण के लिए भी यह विचार नहीं करते कि इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति, विकास और मूल भावनाओं में कितना मौलिक अंतर है।

संस्कृति और भ्रामक कल्पना

अंतिम शब्द है संस्कृति । इसके संबंध में सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। वह भ्रम यहां तक फैल गया है कि आजकल संस्कृति माने नाचना-गाना, सिनेमा-थियेटर अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम। आजकल सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के नाम से जो दल विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए भेजे जाते हैं, उनमें केवल नाचना-गाना जानने वाले कलाकार ही होते हैं; कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं माना जाता कि वे भारतीय संगीत अथवा नृत्य को जानते ही हों। क्या यही भारतीय संस्कृति है, जिसका प्रचार करने हेतु एक समय भारत के संत और महर्षि दुर्लक्ष्य हिमालय को लांघकर एशिया के दूर देशों में गए थे? जिसका प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद एकाकी ही अमरीका पहुंच गए थे? आज तो ऐसा लगता है मानो प्रत्येक सिने तारिका विदेशों में जाकर स्वामी विवेकानंद के महान् मिशन की पूर्ति की अधिकारिणी बन बैठी है। यह सब क्यों हो रहा है? केवल इसलिए कि संस्कृति के बारे में हमारी कल्पनाएं स्पष्ट नहीं हैं।

संस्कृति और राष्ट्र

अतः हम विचार करें कि संस्कृति क्या है। यह विचार इसलिए भी करना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति साधारणतया किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और कोई भी राष्ट्र तभी तक जीवित माना जा सकता है, जब तक

उसकी आत्मा उसके भीतर विद्यमान है। केवल बाह्य उपकरणों से राष्ट्र जीवित नहीं रहता। राष्ट्र में रहनेवाले मनुष्य आते-जाते रहते हैं, उनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है। राष्ट्र की भूमि भी उन मनुष्यों के सामर्थ्य के अनुसार कभी उनके पास रहती है, कभी दूसरों के अधिकार में चली जाती है। इन दोनों के घट-बढ़ से राष्ट्र के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि एक बार ये दोनों बने रहे, पर 'संस्कृति' समाप्त हो गई तो राष्ट्र जीवन का अंत समझना चाहिए। जिस प्रकार आत्मा निकल जाने के पश्चात् अत्यंत हट्टा-कट्टा शरीर भी किसी अर्थ का नहीं रहता, उसी प्रकार संस्कृति के समाप्त होने के बाद अन्य तत्त्व शेष नहीं रहें तो भी राष्ट्र नष्ट हो जाता है।

राष्ट्र कब मरते हैं?

आजकल लोग कहते हैं कि यूनान का पुराना राष्ट्र समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? यूनान की भूमि जहां की तहां मौजूद है, आज भी नक्शे में उसे देख सकते हैं। वहां लोग भी रहते हैं। वे कोई ऐसे नहीं कि किसी भूकंप में पुराने सब लोगों के यकायक समाप्त हो जाने के उपरांत फिर नए सिरे से किसी दूसरी जगह से लेकर बसाए गए हों। वास्तविकता यह है कि उन्हीं पुराने लोगों की संतान आज भी वहां रहती हैं। किंतु पुरानी संस्कृति समाप्त हो गई, पुराने लोगों की जीवन-प्रणाली नष्ट हो गई। अतः हम कहते हैं कि यूनान का पुराना राष्ट्र मर गया। इसी प्रकार मिस्र मिट गया रोम का अस्तित्व नहीं बचा। अर्थात् संस्कृति इतना महत्त्वपूर्ण तत्त्व है कि उसके नष्ट होने के संपूर्ण राष्ट्र जीवन का प्रवाह खंडित हो जाता है। अतः उसके मूल रूप का विचार करना अत्यंत आवश्यक है।

संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जो कर्म हम करते हैं और उनका जो परिणाम होता है, उसे ही हम संस्कार कहते हैं। दूसरे के कर्म का हमारे मन पर जो परिणाम होता है, उसे भी संस्कार कहते हैं। साधारणतया संस्कार शब्द में हम बुरे संस्कारों को नहीं गिनते। उन्हें अलग से कुसंस्कार कहकर पुकारते हैं। चरित्रवान और रूपवान के समान ही जब हम किसी व्यक्ति को संस्कारी कहते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि वह अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति है। उसी प्रकार अच्छे संस्कारों के परिणाम और भाव को ही हम संस्कृति कहते हैं।

संस्कृति शब्द की उत्पत्ति

वैसे संस्कृति शब्द थोड़ा नया है अर्थात् अपने पुराने संस्कृत वाङ्मय में यह शब्द नहीं मिलता। कितना नया होते हुए भी वह कम ही प्रचलित है और हिंदुस्तान में लगभग सभी भाषाओं में एकाध को छोड़ दिया जाए तो इस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। संस्कृति शब्द नया होते हुए भी वह शब्द जिसमें इसका घनिष्ठ संबंध है, बहुत पुराना है। वह शब्द है संस्कार। सभी इससे परिचित हैं और थोड़ा भी व्याकरण की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कारों को जो भाव और परिणाम है, वही संस्कृति है। मलयालम भाषा में तो संस्कृति शब्द है ही नहीं। उसके स्थान पर संस्कार शब्द का ही प्रयोग होता है। संस्कारों का जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उनकी मन पर जो अमिट छाप पड़ती है, उसी का समावेश संस्कृति शब्द में होता है।

संस्कार

संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जो कर्म हम करते हैं और उनका जो परिणाम होता है, उसे ही हम संस्कार कहते हैं। दूसरे के कर्म का हमारे मन पर जो परिणाम होता है, उसे भी संस्कार कहते हैं। साधारणतया संस्कार शब्द में हम बुरे संस्कारों को नहीं गिनते। उन्हें अलग से कुसंस्कार कहकर पुकारते हैं। चरित्रवान और रूपवान के समान ही जब हम किसी व्यक्ति को संस्कारी कहते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि वह अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति है। उसी प्रकार अच्छे संस्कारों के परिणाम और भाव को ही हम संस्कृति कहते हैं। व्यक्ति में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार एवं गुण हैं। वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है। इनके कारण उसके चरित्र के अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं। इस संपूर्ण चरित्र, कर्म और संस्कारों का समुच्चय वाचक यानी उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व में अच्छे और बुरे दोनों आ गया, इस पूर्ण व्यक्तित्व में से बुरे को अलग करके जो अच्छा शेष रहता है, उसको शील नाम से अभिप्रेत करते हैं। इन शीलयुक्त संस्कारों का परिणाम ही संस्कृति कहलाता है।

अच्छे-बुरे की कसौटी

किंतु अब प्रश्न उठता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या? देखने पर लगता है कि अलग-अलग मानदंड हैं। इनकी भिन्नता के कारण ही एक देश और दूसरे देश की संस्कृति में अंतर आ जाता है। इसी भिन्नता के परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों के छोटे से लेकर बड़े व्यवहार में भी भेद मालूम पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए हम अपने यहां नमस्कार करते हैं, किंतु अंग्रेज़ किसी संस्कारी भारतीय महिला को नमस्कार करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो कैसा लगेगा? इन छोटी-छोटी चीजों को लेकर वहां के राष्ट्र-जीवन की अच्छाई-बुराई का पता चलता है। हमारे प्रधानमंत्री वैसे तो हिंदू संस्कृति पर कतई विश्वास नहीं करते, किंतु इस देश की मिट्टी में जन्म लेने के कारण उनके मन पर कुछ संस्कार तो हैं ही। पिछले दिनों उनकी अमरीका यात्रा के दौरान उन्हें अमरीका में एक भोज दिया गया। उसके भोज में अमरीका के लगभग सभी धनी-मानी लोग एकत्र थे। एक पत्रकार भी वहां उपस्थित था। पत्रकारों की आदत के अनुसार उसने वहां पर उपस्थित सभी धनिकों की माली हैसियत को जोड़कर हिसाब लगाना प्रारंभ किया और नेहरूजी से बोला, इस समय आप इतने करोड़ डॉलरों के मध्य बैठे हैं। पंडित नेहरू को यकायक यह समझ में नहीं आया,

इतने करोड़ डॉलरों के बीच बैठने का क्या मतलब है? बाद में पत्रकार ने जब स्पष्टीकरण किया तो नेहरूजी को उसकी बात बड़ी विचित्र लगी। उन्हें अटपटा लगा कि इस व्यक्ति ने उस सारे भोजन का मापन किया तो केवल डॉलरों में। उन्होंने हंसते हुए कहा, "हमारे देश में मापने का यह मापदंड नहीं है। देखने की हमारी दृष्टि दूसरी है। हमने अपने जीवन के आदर्श भिन्न रखे गए हैं।'' इसी दृष्टि भेद की ओर संकेत करते हुए ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इंग्लैंड प्रत्येक चीज को पाउंड, शिलिंग, पेंस में बताता है तो भारत प्रत्येक बात को धर्म की भाषा में बोलता है। एक देश में कालानुसार अच्छे-बुरे की कल्पनाओं का अंतर होता रहता है। अतः किसी काल-विशेष में अच्छे-बुरे की कसौटी यही हो सकती है कि जो अपने जीवन-ध्येय की ओर बढ़ाने में साधक हो, वह अच्छा और जो अपने ध्येय के लिए असाधक हो, वह बुरा। छोटी से छोटी बातों के बारे में निर्णय देते समय भी मनुष्य को अपने ध्येय को ध्यान में रखना पड़ता है।

जीवन-ध्येय क्या?

अतः अब विचार करना पड़ेगा कि अपना ध्येय क्या जिसके अनुसार हम अच्छे-बुरे का निर्णय करें। भिन्न-भिन्न देशों की जीवन पद्धति में जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्यों? क्या यह परिस्थिति वश अकस्मात् हो गई अथवा उसके पीछे जीवन की कोई ध्येयोन्मुखी प्रक्रिया है? जो ईश्वर-विश्वासी हैं, वे यह मान सकते हैं, ईश्वर की सृष्टि उसका योजनाबद्ध प्रयास है। उसने जो कुछ भी बनाया है, वह एक-दूसरे के पूरक के नाते बनाया है। यदि कोई ईश्वर को न माने तो प्रकृति में भी यह दिखता है कि यह एक ऐसा चक्र है, जहां सब एक-दूसरे के पूरक हैं। एक प्रकार से यहां सब लोगों के कार्य (Function) एक-दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र की प्रकृति, विशिष्टता और जीवन-दृष्टि तथा ध्येय भगवान् की योजनानुसार ही निश्चित हुआ होगा। हमारे समाज शास्त्र में यह स्वीकार किया गया है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक जाति समुह अपने जीवन में कुछ विशेषताएं लेकर उत्पन्न हुआ है। हम यह नहीं मानते कि बंदर से आगे जाकर मनुष्य बना। न ही हम यह मानते हैं, स्वर्ग में आदम हौवा नामक स्त्री-पुरुष के जोड़े से मानव जाति उत्पन्न हुई। हम लोग तो यह मानकर चलते हैं। कि सृष्टि के आदिकाल एवं बाद में भी जातियां पैदा होती रही हैं। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह करोड़ों लाखों में पैदा हों। यदि एक-दो व्यक्ति पैदा हो गए तो वही एक जाति का प्रतिनिधित्व और विकास करते हैं।

जीवन-दृष्टि की विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक राष्ट्र की सुख की कल्पना भिन्न है। मूलतः कौन सी प्रकृति यह भगवान् के यहां से लेकर आया है, इसी पर उसके सुख का महल खड़ा होता है। इस मूल प्रकृति को चिति कहते हैं। यही राष्ट्र का केंद्र बिंदु (Nucleus) है। शेष सब तत्व इसके लिए पूरक होते हैं। इसके आधार पर जिन-जिन संस्कारों की सृष्टि होती है, उन सबसे एवं उन संस्कारों से बनने वाले भाव को मिलाकर हम संस्कृति कहते हैं।

'चिति'

ये जातियां भगवान की ओर से कुछ निश्चित ध्येय 'Mission' लेकर आती हैं। उसी के साथ भगवान ने शेष सृष्टि भी एक-दूसरे का पूरक करके उत्पन्न की। दांत दिए तो अन्न भी उपजाया, दांत नहीं तो दूध पैदा किया। बटेर पैदा की तो उसके खाने के लिए कीड़े पैदा किए। सांप पैदा हुआ तो उसकी क्षुधा निवृत्ति के लिए मेढ़क भी भेजे। सब एक-दूसरे के पूरक हैं। पता नहीं भगवान का जो यह चक्र चला, उसके साथ क्या योजना है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह योजना विद्यमान है। यदि सब में कवि की प्रतिभा हो तो , संसार का क्या होगा? यदि सब नाचनेवाले ही हो जाएं तो क्या दृश्य पैदा होगा? कहने का अर्थ यह है कि गुणों और प्रतिभाओं का विभाजन किया और उन्हें एक-दूसरे का पूरक बनाया। इसी प्रकार जातियों के बारे में है। जाति का सही पर्याय कास्ट नहीं है। प्रत्येक जाति भगवान् के पास से कुछ विशेषता लेकर आती है। वह विशिष्ट भावना उस जाति के प्रत्येक मनुष्य में अल्पाधिक मात्रा में विद्यमान रहती है, जो नए लोग उसमें समाविष्ट होते हैं, उन्हें भी दया-धर्म के अनुसार मिलती है और उसी जातिगत वैशिष्ट्य या भावना को अपने यहां एक तकनीकी नाम 'चिति' दिया गया है। यही राष्ट्र की मूल भावना है, जो राष्ट्र के प्रत्येक घटक में सामान्य तत्त्व (Common factor) के रूप में रहती है। यह जीवन की एक दृष्टि है। इसी दृष्टि के आधार पर जीवन के सुख की कल्पना की गई है। यदि इस दृष्टि के अनुसार सुख मिला तो जीवन सफल, अन्यथा नहीं।

जीवन-दृष्टि की विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक राष्ट्र की सुख की कल्पना भिन्न है। मूलतः कौन सी प्रकृति यह भगवान के यहां से लेकर आया है, इसी पर उसके सुख का महल खड़ा होता है। इस मूल प्रकृति को चिति कहते हैं। यही राष्ट्र का केंद्रबिंदु (Nucleus) है। शेष सब तत्त्व इसके लिए पूरक होते हैं। इसके आधार पर जिन-जिन संस्कारों की सृष्टि होती है, उन सबसे एवं उन संस्कारों से बनने वाले भाव को मिलाकर हम संस्कृति कहते हैं। अर्थात् यह चिति ही परम सुख की कल्पना का आधार है। इस चिति की अनुभूति के लिए ही मनुष्य सब कार्य करता है। संस्कृति एक गतिमान (Dynamic) कल्पना है, यह वर्द्धमान है, व्यापक है तो चिति स्थायी होती है। वह भगवान् केंद्रबिंदु Nucleus के रूप में जितनी प्राप्त होती है, उतनी ही रहती है। वह हम को दया-धर्म के अनुसार मिलती है, चिति के मूल ध्येय की प्राप्ति के लिए जो हम संस्कार डालते हैं, उन संस्कारों का भावात्मक रूप ही संस्कृति कहलाता है। यह वर्द्धमान है, गतिशील है। ■

(-पाञ्चजन्य, जुलाई 6, 1959)

विचारक देवेन्द्र स्वरूप नहीं रहे

(30 मार्च, 1926–14 जनवरी, 2019)

देश के जाने माने इतिहासकार, वरिष्ठ पत्रकार, स्तम्भकार व विचारक श्री देवेन्द्र स्वरूप का निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वांस लेने में तकलीफ होने के चलते उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम श्वांस ली।

श्री देवेन्द्र स्वरूप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चलता-फिरता इन्साइक्लोपीड़िया कहा जाता था। एक समय में संघ के प्रचारक रहे देवेन्द्र स्वरूप को द्वितीय सरसंघचालक गुरूजी से लेकर निवर्तमान सरसंघचालक सुदर्शन जी का बहुत सान्निध्य व स्नेह प्राप्त था। वे राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे भाऊराव देवरस के भी अत्यंत निकट

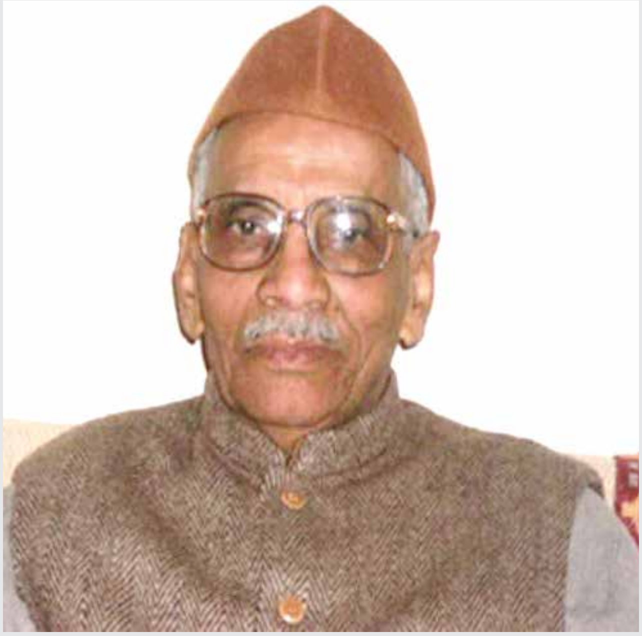

थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पांचजन्य का संपादन भी किया था। इसके बावजूद वे प्रयत्नपूर्वक राजनीतिक क्षेत्र से दूर रहे। श्री देवेन्द्र स्वरूप गहन अध्येता व इतिहासकार होने के साथ ही संविधान रचना के भी जानकार थे। उनके निजी संकलन में ही 15 हजार से अधिक पुस्तकें थीं, जो उन्होंने अस्वस्थ होने के बाद आईजीएनसीए के ग्रंथागार को भेंट कर दीं। अनेक विषयों पर कुल मिलाकर डेढ़ दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखीं थीं। ■

शोक संदेश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक और पाञ्चजन्य के पूर्व सम्पादक श्री देवेन्द्र स्वरूप जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। देवेन्द्र स्वरूप जी ने अपने राष्ट्रवादी विचारों व अद्वितीय लेखन प्रतिभा से एक बौद्धिक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनायी। राष्ट्र और विचारधारा को समर्पित देवेन्द्र स्वरूप जी का सादगीपूर्ण जीवन और उनके विचार हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। मैं दुःख की इस घड़ी में उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

– **अमित शाह,** भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

जीवन–परिचय

श्री देवेन्द्र स्वरूप मुरादाबाद (उ.प्र.) के कांठ कस्बे में 30 मार्च, 1926 को जन्मे। प्रारांभिक शिक्षा कांठ और चंदौसी के विद्यालयों में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागी होने के कारण दो बार विद्यालय से निष्कासन हुआ। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से बी.एससी. करते समय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने का संकल्प लिया। 1947 से लेकर 1960 तक संघ के प्रचारक रहे। गांधीजी की हत्या के पश्चात संघ पर लगे पहले प्रतिबन्ध के दौरान 6 माह तक कारावास में बंदी। संघ की योजना से ही 1958 में हिंदी साप्ताहिक पांचजन्य के संपादन से जुड़े। लखनऊ विवि से इतिहास से एम.ए.। 1964 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पी.जी.डी.ए.वी. कालेज में इतिहास विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1991 में सेवानिवृत्त। इस दौरान दिल्ली प्रदेश अ.भा. विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष रहे। 1968 से 1972 तक बतौर अवैतनिक सम्पादक पांचजन्य के संपादन का कार्य भी किया। श्री स्वरूप आपातकाल में भी एक बार फिर बंदी बनाए गए। 1980 से 1994 तक दीनदयाल शोध संस्थान के निदेशक व उपाध्यक्ष रहे। इस दौरान संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका "मंथन" (अंग्रेजी व हिंदी) के सम्पादन का भी कार्य किया। बतौर इतिहासकार भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् से भी जुड़े रहे। अनेक पुस्तकों के लेखक, संपादक व संकलनकर्ता। पद-पुरस्कार-सम्मान के सभी आग्रहों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार किया।

राजनीतिक स्थिरता, निर्णायक नेतृत्व और एक स्पष्ट जनादेश का सीधा संबंध है विकास के साथ...

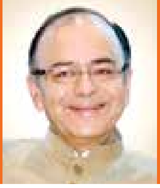

अरुण जेटली

स्वाधीनता के बाद भारत के आर्थिक अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें साल 1991 इस विभाजन का केंद्र बिन्दु रहा। विनियमित अर्थव्यवस्था ने चालीस वर्षों तक भारत की विकास की गति को प्रतिबंधित किया। 1951-52 से 1990-91 तक, भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना 4.2% की वृद्धि हुई। प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति आय में 2% की वृद्धि हुई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1969-70 से 1990-91 तक लगभग दो दशक के दौरान 8.2% की दर से बढ़ा। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 1980-81 से 1990-91 तक दस साल की अवधि के लिए औसतन 6.5% था। उदारीकरण की शुरूआत से पहले बाहरी ऋण हमारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 28.7% था।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने न केवल जीडीपी विकास दर में सुधार किया, बल्कि लाखों लोगों को गरीबी के चंगुल से भी बाहर निकाला और बड़ी संख्या में भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार देखा गया।

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। फिर भी हम 7 से 7.5% की विकास दर से संतुष्ट नहीं हैं। हम तेजी से अधीर हो रहे हैं और 8% के अवरोध को तोड़ना चाहते हैं। इन पांच सालों में हम व्यापार रैंकिंग में 142 वें स्थान से 77 वें स्थान पर पहुंच गए है। हमें अब पहले 50 स्थानों में अपनी जगह बनानी है।

उदारीकरण के बाद, विभिन्न प्रधानमंत्री के अधीन रही सरकारों के जीडीपी विकास और मुद्रास्फीति के आंकड़ों से संबंधित विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण आकंड़े सामने आते है। यह इस प्रकार हैः

अवधि	जीडीपी वृद्धि	मुद्रास्फीति	प्रधानमंत्री
1991-92 से 1995-96	5.1	10.2	पी.वी.नरसिम्हा राव
1996-97 से 1997-98	5.8	8.1	एच.डी.देवेगौड़ा / आई.के.गुजराल
1998-99 से 2003-04	5.9	5.4	अटल बिहारी वाजपेयी
2004-05 से 2008-09	6.9	5.7	मनमोहन सिंह
2009-10 से 2013-14	6.7	10.1	मनमोहन सिंह
2014-15 से 2018-19	7.3	4.6	नरेंद्र मोदी

उपरोक्त आकंड़ों का विश्लेषण करते समय, दो महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान जीडीपी विकास दर में 7.3% की औसत वृद्धि अपने पूर्ववर्तियों प्रधानमंत्रियों की तुलना में बहुत अधिक है। और उच्च विकास दर का प्रभाव पड़ता है। दूसरे, यूपीए-2 के पांच वर्षों के दौरान, मुद्रास्फीति की दर 12.2% और 8.4% के बीच झूलती रही थी। 2013-14 में, यूपीए सरकार ने 9.4% की वार्षिक मुद्रास्फीति के साथ सत्ता को हमारे हवाले किया। इस आंकड़े को नियंत्रित करने में समय लगा। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच वर्षों के कार्यकाल में मुद्रास्फीति का यह आंकड़ा क्रमशः 5.9%, 4.9%, 4.5%, 3.6% और 3.9% रहा है। वर्तमान एनडीए सरकार के पहले वर्ष में इसे नियंत्रण में लाने के साथ ही हम लगातार इस दिशा में काम करते रहे। मोदी सरकार ने मुद्रास्फीति की सीमा के रूप में 4% +/- 2% का

सांविधिक मुद्रास्फीति लक्ष्य तय किया।

जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, तो भारत को जीडीपी के मामले में दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था। वर्तमान में, पांचवीं, छठी और सातवीं अर्थव्यवस्था के तौर पर क्रमशः यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत के बीच बहुत ही संकीर्ण अंतर हैं। मुद्रा मूल्यों का मामूली उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्थाओं के आकार को बदल देता है। बेशक, भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले वर्ष 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर काबिज हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत का राजकोषीय ढांचा किसी भी पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में सबसे अच्छा रहा है। मैकिन्से इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में भारत के मध्यवर्ग का आकार साल 2005 के 14% से बढ़कर 29% हो गया, और यह निरंतर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2025 में यह आकंडा 44% हो जाएगा।

ग्रामीण भारत में पिछले पांच वर्षों में संसाधनों के हस्तांतरण के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक बड़ा आकांक्षावादी वर्ग उभर रहा है।

यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दशकों में हमारे नागरिकों का सामाजिक स्तर और क्रय शक्ति कैसी होने वाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अनुमानित प्रगति सही दिशा में चलती रहे, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारत को इस दौरान एक निर्णायक नेतृत्व मिले, जो नीति निर्धारण की दिशा में स्थिरता और एक मजबूत सरकार देश को देने में कामयाब हो। कमजोर नेतृत्व के साथ एक अयोग्य गठबंधन जिसका भविष्य संदिग्ध हो, वह कभी भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है।

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। फिर भी हम 7 से 7.5% की विकास दर से संतुष्ट नहीं हैं। हम तेजी से अधीर हो रहे हैं और 8% के अवरोध को तोड़ना चाहते हैं। इन पांच सालों में हम व्यापार रैंकिंग में 142 वें स्थान से 77 वें स्थान पर पहुंच गए है। हमें अब पहले 50 स्थानों में अपनी जगह बनानी है।

अब सवाल यह है कि यदि भारत को यह लक्ष्य हासिल करने है, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, ? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने सहयोगियों के हाथों विवश हो और जिसका समर्थन केवल एक आम प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए किया गया हो या फिर साल 2014 में एक स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता संभालने वाला प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ■

(लेखक केंद्रीय वित मंत्री है)

भाजयुमो का विजय लक्ष्य 2019 अभियान

भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन, सांसद (लोकसभा) ने औपचारिक रूप से विजय लक्ष्य 2019 अभियान का शंखनाद किया।

गत 17 जनवरी को श्रीमती पूनम महाजन ने स्वयं अरुणाचल प्रदेश के छोटे से शहर तवांग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 200 से अधिक स्थानों पर उपस्थित 50 लाख से अधिक युवाओं से सीधा संवाद किया और देश के विकास की गति सुनिश्चित करने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। भाजयुमो दिल्ली के अध्यक्ष सुनील यादव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शिवम छाबड़ा, रोहित चहल, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव सागर मिश्रा, राष्ट्रीय प्रभारी अध्ययन मण्डल दिग्विजय सिंह, अनंत प्रकाश, मनमोहन ठाकुर आदि, दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

यह वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से किया जाने वाला सबसे बड़ा युवा संवाद कार्यक्रम है। देशभर के 20 से अधिक स्थानों से दोतरफा संवाद किया गया और लगभग 180 से अधिक स्थानों से एकतरफा संवाद किया गया। जिन स्थानों पर दोतरफा बातचीत हुई उनमें जम्मू-कश्मीर के लेह, अमृतसर के वाघा बार्डर, गुजरात का कच्छ, राजस्थान का जैसलमेर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, छत्तीसगढ़ का बस्तर, लोकतक और कन्याकुमारी शामिल थे। युवा कार्यकर्ताओं ने इस अनूठे अवसर का पूर्ण लाभ उठाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन से सीधा संवाद किया।

नमो ब्रांड की टी-शर्ट्स और टोपियां पहनकर हज़ारों युवाओं ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम में संवाद किया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भाजयुमो को 2019 के आम चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए विजय लक्ष्य 2019 अभियान का नेतृत्व करने का अवसर दिया है।

श्रीमती पूनम महाजन ने देश भर के युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शानदार प्रयास हैं, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने और दूर-दराज के हिस्सों से 50 लाख युवाओं ने एक साथ एक ही समय पर संवाद स्थापित किया। डिजिटल इंडिया ने संचार-संवाद को सरल बना दिया है। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं के लिए एक वरदान साबित हुई हैं। भारत सरकार की इन योजनाओं ने युवाओं को दुनिया के लिए रोजगार पैदा करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि नए भारत के निर्माण के ध्वजधारक ऐसे हों जो देश में रोज़गार के अवसर का निर्माण कर सकें। भारत का प्रतिभाशील युवा रोज़गार के अवसर को निर्मित करने के योग्य हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सतत मार्गदर्शन में इस देश की 130 करोड़ आबादी की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ■

प्रगति से प्रभावित हुए प्रवासी

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

भारतीय प्रवासी भौगोलिक रूप से दूर अवश्य हैं, लेकिन उनके भावनात्मक लगाव में कोई कमी नहीं है। यह बात काशी में हुए प्रवासी सम्मेलन से उजागर हुई। इस बार के संयोग भी दुर्लभ थे। पहली बार विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रवासी भारतीय विश्व के किसी भी हिस्से में हों, काशी के प्रति उनका भक्तिभाव रहता है। दूसरा संयोग प्रयागराज कुम्भ ने बनाया। वैसे प्रवासी सम्मेलन नौ जनवरी को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कुम्भ आयोजन से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया। प्रवासी भारतीयों के लिए यह भाव विभोर करने वाला निर्णय था। काशी में सम्मेलन और प्रयागराज में कुम्भ ने भी एक प्रकार का संगम बनाया।

तीसरा संयोग यह है कि इसी समय दावोस में विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन हुआ। इसमें भारत की प्रगति को अभूतपूर्व बताया गया। कुछ समय बाद चीन को भी भारत पछाड़ देगा। वैश्विक आर्थिक वृद्धि में भारत का योगदान दोगुना हो गया है। दो हजार आठ में यह योगदान सात प्वाइंट छह प्रतिशत था, अब यह चौदह प्वाइंट पांच प्रतिशत हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने सत्तर अंकों की बढ़ोत्तरी हुई है। अगले कुछ समय में भारत शीर्ष पचास देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। नौ जनवरी, 1915 को गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी तारीख को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। इस बार प्रवासियों को कुंभ की भव्यता दिखाने के लिए तारीख बदली गई।

सम्मेलन स्थल का स्वरूप भी सांस्कृतिक गौरव को रेखांकित करने वाला था। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में प्रवेश के लिए सात द्वार बनाये गए थे। गंगा सागर, पाटलीपुत्र, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, गंगोत्री नामकरण किया गया था। युवा प्रवासी भारतीय और बीएचयू के पांच पांच स्टूडेंट्स के पैनल के बीच राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर संवाद हुआ। भारतीय योग नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, प्राणायाम का अनुसरण कर समूचा विश्व स्वस्थ्य होने का प्रयास कर रहा है। डिजिटल इण्डिया विषय पर पैनल डिस्कशन हुआ। नरेंद्र मोदी के भाषण का सूत्र भी यही था। उन्होंने बताया कि भारत में बड़े आर्थिक सुधार हुए है।

पिछले साढ़े चार वर्ष में पांच लाख, 80 हजार करोड़ रुपये सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये सुधार पहले भी हो सकता था लेकिन नीयत नहीं थी, इच्छाशक्ति नहीं थी। करीब सात करोड़ ऐसे लोगों को हटाया है, जो केवल कागज पर थे और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे। अनेक देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग यहां कागजों में जी रहे थे और कागजों में ही सरकारी सुविधा ले रहे थे। यदि देश पुराने तौर तरीकों से ही चल रहा होता, तो आज भी इस पांच लाख, 78 हजार करोड़ रुपये में से चार लाख, 01 हजार करोड़ रुपये लीक हो रहे होते। अगर व्यवस्था में बदलाव नहीं लाए होते यह राशि उसी तरह लूट ली जाती, जैसे पहले लूटी जाती थी।

पिछले साढ़े चार वर्ष में पांच लाख, 80 हजार करोड़ रुपये सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये सुधार पहले भी हो सकता था लेकिन नीयत नहीं थी, इच्छाशक्ति नहीं थी। करीब सात करोड़ ऐसे लोगों को हटाया है, जो केवल कागज पर थे और सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे।

जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नए सिरे से की थी। तब यह एक दिवसीय कार्यक्रम था। इस बार इस आयोजन को तीन दिवसीय किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में हैं। प्रवासियों को मानवता के सबसे बड़े समागम प्रयागराज कुम्भ और नई दिल्ली में गणतन्त्र दिवस समारोह में ले जाने की प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है।

योगी आदित्यनाथ व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी भारतियों को कुंभ दर्शन का औपचारिक आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से कुंभ में विकास की नई गाथा देखने को मिलेगी। सैकड़ों वर्षों बाद अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन का मौका मिलेगा। प्रवासी भारतीयों को काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती एक काफी टेबल बुक भेंट की गई। योगी आदित्यनाथ ने प्रवासियों से भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने में सहयोग का आह्वान किया। पिछले करीब पौने दो साल में उत्तर प्रदेश अराजकता और अव्यवस्था से निकल चुका है। भारत की बेहतरी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से भारत की साख बढ़ेगी। योगी ने दो वर्षों में यहां हुए सुधारों

से प्रवासियों को अवगत कराया। दो वर्ष में सरकार ने 15 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। छह शहरों में नए एयरपोर्ट बन चुके हैं। जल परिवहन को गति देते हुए वाराणसी से प्रयागराज तक रोरो सेवा जल्दी शुरू हो जाएगी। निवेश के लिए सबसे अच्छा माहौल है। प्रवासियों ने एक जिला एक उत्पाद के तहत हस्तशिल्पियों के हुनर की प्रदर्शनी में दिलचस्पी दिखाई।

योगी ने कहा कि भारत की प्रतिभा विश्व भर में अपना लोहा मनवा रही है। सबसे युवा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके मद्देनजर प्रदेश में सवा नौ लाख युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत में प्रवासियों के लिए असीम अवसर हैं। मातृभूमि की प्रगति में प्रवासी भारतीय भागीदार बनें।

सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ उनकी सांस्कृतिक सहयोग पर वार्ता हुई। वे पंडित दीन दयाल हस्तकला संकुल में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जीवन यात्रा पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी देखने भी गए। राष्ट्रपति ने तीस अतिथियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया।

सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ उनकी सांस्कृतिक सहयोग पर वार्ता हुई। वे पंडित दीन दयाल हस्तकला संकुल में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जीवन यात्रा पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी देखने भी गए। राष्ट्रपति ने तीस अतिथियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया। विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि भारत व मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने प्रवासियों को प्रेरणा दी है। सरकार ने अटल जी के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई है, जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि सुझावों को इकट्ठा करने के लिए है। जो भारत को अपना योगदान देना चाहते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई है। यह सफल आयोजन रहा है। लगभग तीन हजार मेहमान प्रयागराज कुंभ में संगम में डुबकी लगाने के बाद दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। प्रवासी सम्मेलन में लगभग नब्बे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कहा जा सकता है कि यह सम्मेलन अभूतपूर्व था। (हिंस) ■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा

रोजगार सृजन हेतु केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' (पीएमआरपीवाई) से 14 जनवरी, 2019 तक एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा, जो एक रिकॉर्ड उपलब्धि है।

गौरतलब है कि पीएमआरपीवाई की घोषणा 7 अगस्त, 2016 को की गई थी और उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लागू कर रहा है। योजना के तहत सरकार नियोक्ता के योगदान का पूरा 12 प्रतिशत का भुगतान कर रही है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, दोनों शामिल हैं। सरकार का यह योगदान उन नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों के लिए है, जिन्हें ईपीएफओ में 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया हो तथा जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपये तक है।

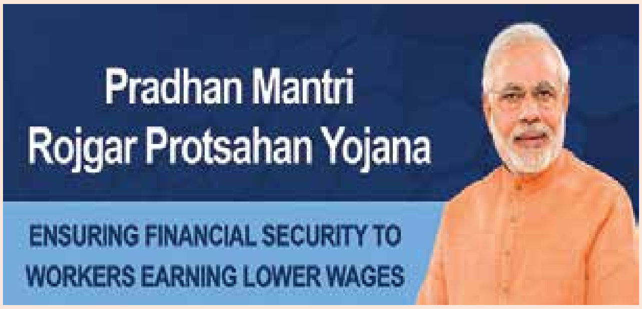

उल्लेखनीय है कि 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (15 जनवरी, 2019 तक) के दौरान क्रमशः 33,031; 33,27,612 और 69,49,436 लाभार्थियों ने पीएमआरपीवाई के तहत ईपीएफओ में पंजीकरण कराया है। योजना के कार्यान्वयन के दौरान लाभांवित होने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 1.24 लाख है। यह पूरी प्रणाली ऑनलाइन और 'आधार' के जरिए चलाई जा रही है। ■

दीनदयाल उपाध्याय : कुशल संगठक व विचारक राजनेता

(25 सितम्बर 1916–11 फ़रवरी 1968)

स्वतंत्र भारत की राजनीति में कुछ ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जो 'विचार और कर्म' दोनों के धनी हों। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो कुशल संगठक तो थे ही साथ ही मौलिक विचारक भी थे। उन्होंने 16 वर्षों तक देशभर में प्रवास करके भारतीय जनसंघ को एक मजबूत संगठन बनाया और साथ ही, 'एकात्ममानव दर्शन' जैसी विचारधारा का प्रतिपादन कर भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय वैचारिक अधिष्ठान भी प्रस्तुत किया।

दीनदयालजी 'सादा जीवन–उच्च विचार' के पुजारी थे। उनकी वेशभूषा सामान्य थी, लेकिन उनके विचार बड़े प्रेरक और प्रखर थे। खद्दर का कुर्ता, धोती, साधारण कैनवास के रबड़ के सोल वाले जूते, मोटा चश्मा, एक सामान्य झोला, जिसमें कुछ किताबें और एक जोड़ी पहनने के कपड़े। आम आदमी की तरह उनकी वेशभूषा थी।

मथुरा जिले के नगला चन्द्रभान ग्राम में 25 सितम्बर 1916 को जन्मे दीनदयालजी ने बचपन से ही विकट परिस्थितियों का सामना किया। ढाई वर्ष की अवस्था में जब वो थे तो पिता का देहांत हो गया। सात वर्ष के थे तो माता जी का निधन। जब वे नवीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब छोटा भाई शिवदयाल का देहांत। 1935 में नानी चल बसी। 1940 में ममेरी बहन का निधन। मृत्यु ने उन पर निरंतर आघात किए, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों का मन मजबूत कर सामना किया।

दीनदयालजी पढ़ने में बहुत तेज थे। मामा राधारमण, जो गंगापुर में सहायक स्टेशन मास्टर थे, के पास रहकर प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई की। दसवीं की परीक्षा कल्याण हाईस्कूल सीकर से दी। वे न केवल प्रथम श्रेणी से उतीर्ण हुए, वरन् समस्त बोर्ड की परीक्षा में वे सर्वप्रथम रहे। 1937 में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में बैठे और न केवल समस्त बोर्ड में सर्वप्रथम रहे, वरन् सब विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की। 1939 में सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर में प्रथम श्रेणी में बीए उत्तीर्ण किया। आगरा में एमए (अंग्रेजी) प्रथम वर्ष में उन्हें प्रथम श्रेणी के अंक मिले। 1941 में 25 की उम्र में बीटी करने प्रयाग गए।

दीनदयालजी 1937 में बीए की पढ़ाई के लिए कानपुर गए, तब अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे के माध्यम से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए, वहीं उनकी भेंट संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार से हुई। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जब कानपुर आए, तो उन्होंने उनको शाखा आमंत्रित कर बौद्धिक वर्ग करवाया। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने तथा संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रचारक बन गए और आजीवन प्रचारक रहे। वे संघ में 1937 से 1951 तक रहे। दीनदयालजी सन् 1952 में जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री बने। 1968 तक 16 वर्ष इस दायित्व को संभाला।

दीनदयालजी स्वाध्यायी प्रवृत्ति थे। जब भी समय मिलता लिखते–पढ़ते रहते थे। दीनदयालजी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में मूल्यों का परिष्कार किया। दीनदयालजी गांव–गांव तक प्रचार करते थे। ज्यादातर रेलगाड़ी में सफर करते थे। ऐसा इसलिए कि एक तो उन्हें पढ़ने–लिखने का समय मिलता था और स्टेशनों पर कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाती थी। दीनदयालजी की कुशल संगठन क्षमता से प्रभावित होकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कहा था, 'यदि मुझे दीनदयालजी जैसे चार–पांच लोग मिल जाएं, तो मैं पूरे देश में जनसंघ को खड़ा कर लूंगा।'

दीनदयालजी का कहना था कि हमारी संस्कृति और परंपरा में दुनिया को देने योग्य क्या-क्या बातें हैं, उन्हें जानें और विश्व की प्रगति में अपना सहयोग दें। लंबे अरसे तक हमारा सारा ध्यान स्वाधीनता संग्राम व आत्मरक्षा में लगा रहा। अतः हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों की बराबरी में खड़े नहीं हो सके हैं, पर आज जब हम स्वतंत्र हैं, तो हमें इस कमी को पूरा करना होगा।

11 फरवरी 1968 के मनहूस दिन दीनदयालजी हमसे विदा हो गए। उनका शव मुगलसराय में पाया गया। संसद में प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शोक प्रस्ताव पारित नहीं होता, जिसका संसद से कोई नाता ना रहे। दीनदयालजी जी ऐसे गिने चुने उन लोगों में रहे, जिनके प्रति संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ■

85,429 करोड़ का बजट पेश, 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम खोला जाएगा

झारखंड विधानसभा में 22 जनवरी को वित्तीय वर्ष 2019-20 का मूल बजट मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने करीब 85,429 करोड़ रु. का पेश किया। इस बार के बजट में 6182.44 करोड़ रुपये के चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा- अटल बिहारी बाजपेयी के सपनों का झारखंड बनाना है। किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य है। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम खुलेगा। श्री रघुवर दास लगातार पांचवीं बार बजट पेश करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं।

बजट की मुख्य बातें

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 85 हजार 429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 65 हजार 803 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत व्यय के लिए 19 हजार 626 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 23 हजार 377, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 28 हजार 882 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 33 हजार 170 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए हैं।

-वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.73 प्रतिशत वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय 83 हजार 513 रुपए का आकलन है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 76 हजार 806 रुपए और 2019-18 में 70 हजार 728 रुपए था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 7 हजार 155.63 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.26 प्रतिशत है।

- राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, गव्य, मत्स्य, लाह, तसर, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन, हस्तशिल्प, ऊर्जा एंव सिचाई प्रक्षेत्रों को कवरेज करते हुए पहली बार वर्ष 2016-17 में कृषि बजट की परिकल्पना की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कृषि बजट 7 हजार 231.40 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.51 प्रतिशत अधिक है।

-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास बजट 24,410.06 करोड़ रुपए था। 2019-20 में ये बजट बढ़कर 27,142.60 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है। 2019-20 के बजट में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 6182.44 करोड़ रुपये के चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जेंडर बजट के रूप में 8,898.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 8.59 प्रतिशत अधिक है।

- राज्य में 1,200 किसानों को मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि से मीठी क्रांति नाम की योजना शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 करोड़ रुपए की राशि से मीठी क्रांति का लाभ 12 हजार किसानों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

-साथ ही झारखंड में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर सुजलाम सुफलाम योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सूखाग्रस्त जिलों में नाला, झील, डैम एवं तालाबों का निर्माण किया जाएगा, ताकि इन ढांचों की मदद से पानी की क्षमता को बढ़ाकर कृषि कार्य में मदद लिया जा सके।

- कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए राज्य के सभी जिलों में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के एक-एक शीतगृह का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। अब तक 14 जिलों में शीतगृह का निर्माण चल रहा है।

-वित्तीय वर्ष 2019-20 में खूंटी, सरायकेला-खरसांवा, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, दुमका, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिलों में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के शीतगृह का निर्माण कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 46 प्रखण्ड में कोल्ड रूम का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 प्रखण्डों में कोल्ड रूम का निर्माण करने का लक्ष्य है।

-झारखंड के हर जिलों में शीत गृह का निर्माण, टाना भगतों को शत-प्रतिशत अनुदान पर चार गाय दी जाएगी।

-मछली पालन तकनीक का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इन तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा।

-2100 मछुवारों को आवास की सुविधा दी जाएगी। कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना शुरू की जाएगी।

-मछली पालकों और सखी मंडलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। एक लाख से ज्यादा मछली पालों का बीमा किया जाएगा।

- निर्भया फंड के तहत 21 जिलों में में वन स्टॉप सेंटर। 100 प्रखंडों में कोल्ड रूम खुलेगा।

- उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर, बोकारो और दुमका से विमान सेवा।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में डेढ़ लाख पीएम आवास बनाने का लक्ष्य।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3 हजार बिरसा आवास बनाने का लक्ष्य।

- 81.25 प्रतिशत हुई राज्य की साक्षरता दर।

- 263 प्रखंडों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण। ■

केंद्र सरकार ने प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया: नरेन्द्र मोदी

पिछले साढ़े चार वर्षों में लोगों के खातों में सीधे 5,80,000 करोड़ रुपये का ट्रांसफर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी को वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के पूर्ण सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 के मुख्य अतिथि मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाइक, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, प्रवासी भारतीय मामलों के राज्य मंत्री श्री वी.के.सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी भारतीयों का अपने पूर्वजों की भूमि के प्रति प्यार और लगाव है जो उन्हें भारत लाया है। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय से नए भारत के निर्माण में हाथ बंटाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा को जीवित रखने में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय न केवल भारत के ब्रांड एम्बेसेडर हैं, बल्कि भारत की शक्ति, क्षमताओं और विशेषताओं के प्रतिनिधि भी हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय से नए भारत विशेषकर अनुसंधान और नवाचार में नए भारत के निर्माण में भागीदारी करने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने कहा कि तेज प्रगति के साथ भारत को विश्व में ऊंचे स्थान पर देखा जा रहा है और भारत वैश्विक समुदायों के नेतृत्व करने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऐसा एक उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र स्थानीय समाधान और वैश्विक प्रयोग है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड की दिशा में एक कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक पावर हाउस बनने के मार्ग पर है। भारत के पास सबसे बड़ी स्टार्ट-अप प्रणाली और विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। हम तेजी के साथ मेक इन इंडिया की ओर बढ़ चुके हैं। आवश्यकता से अधिक फसल हमारी प्रमुख उपलब्धि है।

श्री मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की इच्छा शक्ति और उचित नीतियों की कमी के कारण लाभार्थियों के लिए निर्धारित धन उनके लिए उपलब्ध नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी की मदद से प्रणाली में खामियों को रोक दिया है। सार्वजनिक राशि की लूट रोक दी गई है और 85 प्रतिशत खोई हुई राशि उपलब्ध कराई गई है और सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में लोगों के खातों में सीधे 5,80,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह सात करोड़ फर्जी नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए गए हैं। यह लगभग ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की आबादी के बराबर है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन नए भारत के नए विश्वास को दिखाते हैं।

पिछले साढ़े चार वर्षों में लोगों के खातों में सीधे 5,80,000 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं। सात करोड़ फर्जी नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए गए हैं। यह लगभग ब्रिटेन, फ्रांस और इटली की आबादी के बराबर है। उनकी सरकार द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन नए भारत के नए विश्वास को दिखाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय नए भारत के हमारे संकल्प में समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा हमारी चिंता है। उन्होंने बताया कि किस तरह सरकार ने संघर्ष वाले क्षेत्रों में फंसे पड़े दो लाख से अधिक भारतीयों को वहां से निकालने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के कल्याण के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पासपोर्ट और वीज़ा नियम सरल बनाए गए हैं और ई-वीज़ा ने उनकी यात्रा को और आसान बना दिया है। अब सभी प्रवासी भारतीय पासपोर्ट सेवा से जोड़े जा रहे हैं और चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों से पांच गैर-भारतीय परिवारों को भारत भ्रमण के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से गांधी जी और गुरूनानक देव जी के मूल्यों का प्रसार करने और उनकी जयंती समारोहों का हिस्सा बनने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गर्व होता है कि बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन के संकलन में वैश्विक समुदाय शामिल हुआ।

प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस को सफल बनाने में काशी के निवासियों की गर्मजोशी और अतिथ्य सत्कार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बताया कि आगामी स्कूल बोर्ड परीक्षाओं से पहले वह माता-पिता तथा विद्यार्थियों से 29 जनवरी, 2019 को 11 बजे परीक्षा पे चर्चा में नमो ऐप्प के माध्यम से बातचीत करेंगे।

प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के मुख्य अतिथि मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ ने भारतीय समुदाय की स्मृतियों तथा उनके पूर्वजों की भूमि से जुड़ाव की चर्चा की। उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी में कहा कि इस तरह के अवसर प्रवासी भारतीयों की पहचान साझा इतिहास और संस्कृति के साथ एक परिवार के सदस्य के रूप में करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत अनूठा है तो भारतीयता सर्वव्यापी है।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षित और आत्मनिर्भर प्रवासी भारतीय समुदाय राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकता है और समुदाय के जुड़ाव से बहुपक्षवाद को मदद मिल सकती है। उन्होंने भोजपुरी में बोलकर लोगों को प्रफुल्लित किया और घोषणा की कि मॉरीशस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी उत्सव का आयोजन करेगा।

विदेशमंत्री ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गर्व का अनुभव करता है। उन्होंने मातृभूमि के साथ जुड़ाव के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस और कुंभ एक भारत, श्रेष्ठ भारत को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने 'भारत को जानिये' क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। यह युवा प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए क्विज प्रतियोगिता है। ■

प्रधानमंत्री ने वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केन्द्रों का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी को वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केन्द्रों का उद्घाटन किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से सीधे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने 55 केन्द्रों के उद्घाटन के अवसर पर पट्टिका का अनावरण किया। यह केन्द्र क्षेत्र की हस्तकला को समर्पित परिसर हस्तकला संकुल में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में सेवा देंगे। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल हस्तकला संकुल में एमपीथियेटर पहुंचने से पहले टेक्सटॉइल म्यूजियम की गैलरियों को देखा।

प्रधानमंत्री ने दो पुस्तकों (ए) काशीः यूनिवर्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स (बी) इंडियन टेक्सटाइल्स : हिस्ट्री, स्प्लेन्डर ग्रैन्डूर-का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने चौकाघाट में एकीकृत टेक्सटाइल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन अवसर पर पट्टिका का अनावरण किया।

लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग का अनुपम संगम है भारतः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जनवरी को गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी प्रदर्शनी सह सम्मेलन केन्द्र में वाइब्रेंट गुजरात के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान, रवांडा, डेनमार्क, चेक गणराज्य और माल्टा के राष्ट्र प्रमुख उपस्थित थे। इसके अलावा उद्योगजगत के प्रतिनिधियों समेत 30 हजार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं।

श्री मोदी ने उद्योगजगत के प्रतिनिधियों तथा कंपनियों को भारत आने और यहां निवेश करने का आमंत्रण दिया, क्योंकि अवसंरचना और सुविधाएं बेहतर हुई हैं और व्यापार की स्थिति निवेशक अनुकूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान 'व्यापार करने में आसानी' श्रेणी में भारत ने 65 स्थानों की छलांग लगाई है। भारत को आने वाले वर्षों में इस श्रेणी के 50वें स्थान तक लाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के लिए किए गए सुधारों में विश्वास व्यक्त किया है। जीएसटी के कार्यान्वयन से लेनदेन की लागत में कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की औसत विकास दर 7.3 प्रतिशत है जो 1991 के बाद से सर्वाधिक है। इसी के साथ औसत महंगाई दर 4.6 प्रतिशत है जो 1991 के बाद से न्यूनतम है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान मेरी सरकार का लक्ष्य प्रशासन को बढ़ाना और सरकार को कम करना रहा है। हम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार कर रहे हैं। हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में स्टार्ट अप का सबसे बड़ा परितंत्र है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से मेक इन इंडिया पहल को सहायता मिली है।

श्री मोदी ने कहा कि 2017 में भारत में रिकॉर्ड पर्यटक आए हैं। 2016 की तुलना में पर्यटकों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पूरे विश्व के संदर्भ में केवल 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले चार वर्षों के दौरान हवाई यात्रा में दस से अधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत असीम संभावनाओं वाला देश है। यह एक मात्र देश है जो लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग का विकल्प देता है।

वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रमुखों की उपस्थिति से यह एक वैश्विक मंच बन गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों की राजधानियों तक हो गया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और नीति आधारित प्रशासन की सराहना करते हुए उद्योगजगत के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि व्यापार को आसान बनाने के लिए हरसंभव सहायता व सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शौकत मिरजियोयेव, डेनमार्क के प्रधानमंत्री श्री लार्स लोक रासम्युसिन, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री आंद्रेज बबिज और माल्टा के प्रधानमंत्री डॉ. जोसेफ मस्कट भी उपस्थित थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक विशेष संदेश देते हुए कहा कि गुजरात हम दो व्यक्तियों के बीच सुदृढ़ सम्बन्ध को रेखांकित करता है। हम दोनों साथ मिलकर भविष्य के लिए असीम संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं।

गौरतलब है कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन 2003 में किया गया था। उस समय श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात में निवेश को आकर्षित करना था। ■

प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा में 1500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जनवरी को ओडिशा में बलांगीर का दौरा किया। उन्होंने 1500 करोड़ रुपये की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और इसके साथ ही कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बलांगीर में प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) राष्ट्र को समर्पित किया। यह मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क इस क्षेत्र में झारसुगुड़ा को लॉजिस्टिक्स के प्रमुख केन्द्र (हब) के रूप में स्थापित कर देगा। श्री मोदी ने रेल परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुए 115 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली बलांगीर-बिचुपली रेल लाइन का भी उद्घाटन किया।

ओडिशा की आम जनता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पिछले तीन हफ्तों में ओडिशा की उनकी तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री ने बलांगीर स्थित रेलवे यार्ड में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, 'सरकार पूर्वी भारत और ओडिशा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। बलांगीर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ इस दिशा में एक ठोस कदम है।'

प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही नागावेली नदी पर बने नये पुल, बारापली एवं डुंगरीपली और बलांगीर एवं देवगांव के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण और 813 किलोमीटर लंबी झारसुगुड़ा-विजिनगरम और संबलपुर-अंगुल लाइनों के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के सोनपुर में केन्द्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी, जिस पर अनुमानित 15.81 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

श्री मोदी ने कनेक्टिविटी और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'शिक्षा से मानव संसाधन का विकास होता है और ये संसाधन तब अवसर में तब्दील होते हैं, जब उसे कनेक्टिविटी का सहारा मिलता है। छह रेल परियोजनाओं का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में हमारा एक ठोस प्रयास है। इससे लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी, उद्योग जगत के लिए खनिज संसाधन और ज्यादा सुगम्य हो जाएगे और इससे किसानों को दूरदराज के बाजारों में भी अपनी उपज को ले जाने में मदद मिलेगी, जिससे ओडिशा के नागरिकों के लिए जीवन-यापन और ज्यादा आसान हो जाएगा।'

श्री मोदी ने संस्कृति और धरोहरों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे हमारे सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे और इसके साथ ही इस राज्य में पर्यटन की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने गंधरादी (बौध) स्थित नीलमाधव और सिद्धेश्वर मंदिरों में किये गये जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने बलांगीर में स्मारकों के रानीपुर झरियाल समूह और कालाहांडी में असुरगढ़ किले के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्यों का भी शुभारंभ किया। ■

लाल किले में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन

स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को याद करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की और लाल किले में नेताजी सुभाष संग्रहालय का उद्घाटन किया।

गौरतलब है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज संग्रहालय सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। संग्रहालय में सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज से संबंधित विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इनमें लकड़ी की कुर्सी और नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार, पदक, बैच, वर्दी तथा आजाद हिन्द फौज से संबंधित सामग्री है। इस संग्रहालय की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 21 अक्तूबर, 2018 को रखी थी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। वह महान हस्ती थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प किया और सम्मान के साथ जीवन जिए। हम उनके आदर्शों को पूरा करने और मजबूत भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।"

> **@narendramodi**
>
> **मैं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। वह एक ऐसे महान हस्ती थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया और गरिमामय जीवन जीए। हम उनके आदर्शों को पूरा करने और एक सुदृढ़ भारत का निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।**

उन्होंने कहा कि इन दीवारों से इतिहास गूंजता है। इसी भवन में भारत के बहादुर सपूत कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाह नवाज खान पर औपनिवेशिक शासकों ने मुकदमा चलाया था। प्रधानमंत्री ने सुभाष चन्द्र बोस और आजाद

हिन्द फौज के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली तस्वीरों को भी देखा।

श्री मोदी ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज से जुड़ी चीजें भी देखीं। इनमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी, तलवार, पदक, बैच और आजाद हिन्द फौज की वर्दी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने याद-ए-जलियां संग्रहालय में जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड को चित्रित करने वाली तस्वीरें, पेंटिंग तथा समाचार पत्र को देखा। यह संग्रहालय 1919 में हुए जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के बलिदान को इतिहास के रूप में प्रस्तुत करता है।

श्री मोदी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर बने संग्रहालय भी गए और 1857 में भारतीय लोगों द्वारा दिखाए गए शौर्य और बलिदान की प्रदर्शनी को भी देखा। यह संग्रहालय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को दिखाता है।

प्रधानमंत्री ने भारतीय कला पर प्रदर्शनी को दृश्यकला संग्रहालय में देखा। उन्होंने कहा दृश्यकला में गुरूदेव टैगोर की कृतियों के देखकर कला प्रेमी आनंदित होंगे। हम सभी जानते हैं कि गुरूदेव टैगोर बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन कला संसार से भी उनका काफी लगाव था। उन्होंने अनेक कृतियों में विविध विषयों के प्रस्तुत किया। उनकी कृतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई गईं।

प्रधानमंत्री ने ट्विट किया, "मैं कला प्रेमियों से विशेषकर आग्रह करुंगा कि वे दृश्यकला संग्रहालय जाएं जो भारतीय और कला संस्कृति के बेहतरीन पहलुओं की झलक दिखाता है। प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा, गुरूदेव टैगोर, अमृता शेरगिल, अबनिन्द्र नाथ टैगोर, नन्दलाल बोस, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, सैलोज मुखर्जी तथा जामिनी रॉय जैसे कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई हैं।"

संग्रहालयों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति से जुड़े चार संग्रहालय का उद्घाटन करके अत्यधिक प्रसन्नता हुई। सभी चार संग्रहालयों को कला मंदिर का नाम दिया गया है। इस परिसर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज संग्रहालय, याद-ए-जालियां संग्रहालय (जालियांवाला बाग और प्रथम विश्व युद्ध), भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर संग्रहालय और तीन शताब्दियों की 450 से अधिक कलाकृतियों वाला दृश्यालय संग्रहालय शामिल है।

क्रांति मंदिर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के क्रांतिकारी उत्साह और साहस के प्रति श्रद्धांजलि है। गणतंत्र दिवस से पहले ये संग्रहालय हमारे युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ेंगे और नागरिकों में देशभक्ति का भाव भरेंगे।

कांग्रेस ने कभी नहीं किया अम्बेडकर का सम्मान : थावरचंद गहलोत

केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 6 जनवरी को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश पर 60 साल राज करने वाली पार्टी ने कभी बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने यह काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े पांच स्थानों जिसमें जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण और अन्तिम संस्कार स्थल शामिल हैं, को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित किया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अनुसूचित मोर्चा द्वारा आयोजित भीम महासंगम में पार्टी नेताओं ने विपक्षी दलों पर अनुसूचित जाति के समाज की उपेक्षा करने को लेकर जमकर निशाना साधा। वहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री बनाने का भी संकल्प लिया। इस मौके पर समरसता

खिचड़ी भी तैयार की गई। नागपुर के श्री विष्णु मनोहर ने एक विशाल बर्तन में पांच हजार किलो खिचड़ी तैयार की। भाजपा नेताओं ने भारत माता के चित्र पर इसका भोग लगाने के बाद भीम महासंगम में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ इसका सेवन किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक तीन हजार किलो भोजन एक ही बर्तन में बनाने का रिकॉर्ड नागपुर के शेफ श्री विष्णु मनोहर के नाम है। उन्हीं मनोहर जी ने आज यहां पांच हजार किलो खिचड़ी एक ही बर्तन में बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि अम्बेडकर का मानना था कि किसी के साथ भेदभाव करके समाज में समता और समरसता का माहौल नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में अंत्योदय की योजना इसी उद्देश्य को लेकर शुरू की गई थी। वर्तमान मोदी सरकार भी उसी सोच को साकार करने की दिशा में अग्रसर है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल को समर्थन देने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ता तीन लाख घरों में गए। साढ़े चार साल के मोदी सरकार के कार्यों से खुश जनता ने उन्हें एक और कार्यकाल देने के समर्थन के रूप में एक मुट्ठी चावल और आधी मुट्ठी दाल थी।

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) महामंत्री श्री रामलाल ने कहा कि हर कार्यकर्ता यह संकल्प लेकर जाए कि वह दस-दस परिवारों के बीच जाकर उन्हें प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगा। सभी को साथ जोड़ने का कार्य करेगा और दिल्ली में कमल खिलाकर नरेन्द्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में जुट जाएगा।

उन्होंने कहा कि अम्बेडकर और मोदी दोनों का विचार समाज को जोड़ने का है। दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सम्मान का जब प्रश्न आता है तो वह कांग्रेस, मायावती और मुलायम सिंह, ममता बनर्जी और केजरीवाल पीछे क्यों हट जाते हैं। राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर ही अम्बेडकर से जुड़े स्थानों का विकास हुआ।

दिल्ली भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री मोहनलाल गिहारा ने कहा कि अलग-अलग जातियों में बंटे दलित समाज ने भीम महासंगम के माध्यम से यहां एक साथ पहुंचकर अपनी एकता का संदेश दिया है।

भीम महासंगम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वश्री दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, डॉ. अनिल जैन, सांसद डॉ. उदित राज, प्रवेश वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, मिजोरम के प्रभारी श्री पवन शर्मा, दिल्ली भाजपा संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन आदि उपस्थित रहे। ■ (हि.स.)

राष्ट्र निर्माण में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जनवरी को मुम्बई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी. विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री देवेन्द्र फणनवीस, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय युवा पीढ़ी को भारतीय सिनेमा को समझने और उसके बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि संग्रहालय में विभिन्न फिल्मी हस्तियों के संघर्ष की गाथाओं के साथ-साथ भारतीय मनोरंजन उद्योग के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी होगी।

यह कहते हुए कि फिल्म और समाज एक दूसरे का प्रतिबिम्ब हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में जो कुछ होता है उसकी झलक स्क्रीन पर सिनेमा में देखने को मिलती है जबकि फिल्मों की छवि समाज के आईने में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक ऐसे फिल्में हैं जो समस्याएं और समाधान दोनों को दर्शाती हैं, जो पिछले उन वर्षों की तुलना में एक सकारात्मक संकेत है जब केवल बेबसी को ही दिखाया जाता था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सॉफ्ट पावर, उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने और दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का निर्माण करने में भारतीय सिनेमा की एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि सिनेमा के जरिए महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे जैसे स्वच्छता, महिला अधिकारिता, खेल आदि लोगों तक पहुंच रहे हैं। सिनेमा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पर्यटन को बढ़ाने में योगदान देने की फिल्म उद्योग में काफी संभावना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विश्वास है कि वह अपने सामने मौजूद समस्याओं का खुद ही समाधान निकाल लेगा और उन्होंने कहा कि यह केन्द्र के विश्वास का संकेत है और वह मुद्दों को उठाकर उनका समाधान निकाल सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच को उजागर किया। इस संदर्भ में उन्होंने विश्व के उन विभिन्न नेताओं के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया जो यहां तक की भारतीय फिल्मों के गीत गा लेते हैं।

उन्होंने ऐसे चरित्रों का निर्माण करने के लिए फिल्मी बिरादरी को शुभकामनाएं दी जो युवा पीढ़ी की कल्पनाओं को समेट लेती है। उन्होंने कहा कि ऐसे चरित्रों की वैश्विक अपील के कारण भारतीय युवा पीढ़ी न केवल बैटमैन की प्रशंसक है बल्कि वह बाहुबली को भी देखना चाहती है।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में फिल्म की शूटिंग को मंजूरी देने के लिए सरकार सिंगल विन्डो क्लीयरेंस प्रणाली लाने के लिए 'ईज ऑफ फिल्मिंग' की सुविधा प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फिल्म पायरेसी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमाटोग्राफ कानून 1952 में संशोधन करने की दिशा में कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक के लिए सरकार एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक पूरी तरह समर्पित संचार और मनोरंजन विश्वविद्यालय समय की मांग है। उन्होंने हस्तियों से आग्रह किया कि वे इस बारे में सुझाव और योगदान दें। उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन की तर्ज पर ग्लोबल फिल्म शिखर सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया, जिससे भारतीय सिनेमा के बाजार का विस्तार हो सकेगा। ■

गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जयंती समारोहों के अवसर पर 13 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में 350 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के उदात्त आदर्शों और मूल्यों- मानवता, भक्ति, वीरता और बलिदान की निस्वार्थ सेवा की सराहना की और लोगों से उनके द्वारा बताये मार्ग पर चलने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती मनाने के लिए स्मारक सिक्का जारी करने के बाद अपने निवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक चुनिंदा सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, दार्शनिक, कवि और गुरु थे। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लोगों को उनके दिये गये उपदेश धर्म और जाति की बाधाओं को तोड़ने पर केंद्रित थे। प्रेम, शांति और बलिदान का उनका संदेश आज भी समान रूप से प्रासंगिक है।

गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, दार्शनिक, कवि और गुरु थे। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लोगों को उनके दिये गये उपदेश धर्म और जाति की बाधाओं को तोड़ने पर केंद्रित थे। प्रेम, शांति और बलिदान का उनका संदेश आज भी समान रूप से प्रासंगिक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके मूल्य और उपदेश आने वाले वर्षों में मानव जाति के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह स्मारक सिक्का हमारी ओर से उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रदर्शित करने का एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने लोगों से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज द्वारा बताये गए 11 सूत्रीय मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से 30 दिसंबर, 2018 के उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की तर्ज पर गुरू गोबिंद सिंह जी द्वारा दिखाये गये देश भक्ति और बलिदान के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। उन्होंने 5 जनवरी, 2017 को पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350 वीं जयंती समारोहों में भाग लिया और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। श्री मोदी ने 15 अगस्त, 2016 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में और फिर 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार समारोह में गुरु गोबिंद सिंह जी के आदर्शों और मूल्यों को मानवता के मूल के रूप में स्मरण किया। ■

प्रधानमंत्री द्वारा दादरा और नगर हवेली में 1400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को दादरा और नगर हवेली में सिलवासा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दादरा और नगर हवेली के सयाली में चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने दादरा और नगर हवेली के लिए आईटी नीति का अनावरण किया। एम-आरोग्य मोबाइल ऐप और हर दरवाजे पर जाकर कूड़ा संग्रह, दादरा और नगर हवेली में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और प्रसंस्करण का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को गोल्ड कार्ड भी वितरित किया और लाभार्थियों को वन अधिकार पत्र बांटा। प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज 1400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं संपर्क, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति और नई आईटी नीति शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने नोट किया कि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली दोनों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। दोनों संघ शासित प्रदेशों को केरोसीन मुक्त भी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज दोनों संघ शासित प्रदेशों में एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, दोनों संघ शासित प्रदेशों के गरीब निवासियों को मकान आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत लाभ के हकदार दोनों संघ शासित प्रदेशों के लोगों को गोल्ड कार्ड भी जारी किए गए हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले 3 वर्षों में दोनों संघ शासित प्रदेशों में 9000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसके कारण कई विकास परियोजनाएं आरम्भ हुई हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय, दादरा और नगर हवेली की आधारशिला रखने के साथ ही दमन और दीव को अपना पहला चिकित्सा महाविद्यालय मिल गया है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष चिकित्सा महाविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि अब तक दोनों संघ शासित प्रदेशों में एक वर्ष में केवल 15 मेडिकल सीटें थीं और इस चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के साथ, अब 150 सीटें उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा।

आयुष्मान भारत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल परियोजना है और हर रोज 10 हजार निर्धन इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसकी स्थापना के बाद से केवल 100 दिनों में 7 लाख से अधिक गरीब रोगियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शहरों और गांवों में गरीबों को एक स्थायी घर प्रदान करने के लिए एक

व्यापक अभियान चल रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में, जिसने 5 साल में केवल 25 लाख घर बनाए थे, हमने 5 साल में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा घर बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि अकेले दादरा और नगर हवेली में 13000 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वन धन योजना के तहत, वन उपज में मूल्य संवर्धन के लिए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि दादरा और नगर हवेली में पर्यटन की बहुत संभावना है। इस क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र में लाने के लिए कई पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए नीली क्रांति के तहत काम किया जा रहा है। मत्स्य क्षेत्र में सुधार के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस कोष के तहत 7500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 125 करोड़ भारतीय उनके परिवार हैं और वह उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ■

किसानों की आमदनी दोगुनी करने में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ का महत्वपूर्ण योगदान : राधा मोहन सिंह

2014–18 के दौरान 551 कृषक उत्पादक कंपनियों का गठन

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने 17 जनवरी को नई दिल्ली में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि भारत के किसान खुशहाल हों और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। इसे साकार करने में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) का कार्य सराहनीय है।

श्री राधामोहन सिंह ने कहा कि लघु, मध्यम एवं सीमांत कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओं) को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में लगभग 5000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन विभिन्न संस्थान जैसे कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), नाबार्ड एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा वर्ष 2014-18 के दौरान 551 कृषक उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है, जो वर्ष 2011-14 में गठित 223 कृषक उत्पादक कंपनियों की तुलना में 147.09 प्रतिशत अधिक है। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 7.52 लाख लघु, मध्यम एवं सीमांत कृषकों को संगठित कर एफपीओं से जोड़ा गया है।

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ द्वारा वर्ष 2014-18 के दौरान 551 कृषक उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है, जो वर्ष 2011-14 में गठित 223 कृषक उत्पादक कंपनियों की तुलना में 147.09 प्रतिशत अधिक है। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 7.52 लाख लघु, मध्यम एवं सीमांत कृषकों को संगठित कर एफपीओं से जोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि एसएफएसी द्वारा इन कृषक उत्पादक संगठनों को अधिक सक्षम एवं मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसेकि पेशेवर प्रशिक्षण, पेशेवर हैंड होल्डिंग, दिल्ली किसान मंडी, एफपीओ-क्रेता ई-इंटरफेस पोर्टल एवं मूलभूत ढांचों के सशक्तिकरण इत्यादि का संचालन किया जा रहा है।

इसके साथ ही एसएफएसी द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पूंजी अनुदान, ऋण गांरटी योजना एवं उद्यम पूंजी सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2014 से अभी तक 349 एफपीओ को 20 करोड़ रुपये की पूंजी अनुदान प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 38 एफपीओ ने ऋण गांरटी योजना का लाभ लिया है। उद्यम पूंजी सहायता के अंतर्गत 2014 तक 850 प्रकल्पों को रुपए 264.32 करोड़ दिए गए थे, जो कि पिछले 4 वर्षों में बढ़कर 1426 प्रकल्पों में रुपए 404.45 करोड़ हो गए। इससे प्रकल्पों में 67.76 प्रतिशत एवं उद्यम पूंजी सहायता राशि में 53.03 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि हुई है।

श्री सिंह ने राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) परियोजना के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना कृषि बाज़ार को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। इसके प्रथम चरण में विभिन्न राज्यों की 585 कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। ई-नाम परियोजना को पूरे देश में विस्तार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 2018-19 में 200 नई मंडिया एवं 2019-20 में 215 नई मंडियों को इस परियोजना से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इस तरह 2020 के अंत तक 1000 मंडियां ई-नाम परियोजना में सम्मिलित हो जाएगी।

उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि 31 दिसम्बर, 2018 तक ई-नाम पर कुल 58930 करोड़ रुपए की 2.25 करोड़ मीट्रिक टन कृषि जिन्सों/उत्पादों का व्यापार हो चुका है तथा 1.41 करोड़ किसान व अन्य विक्रेता इस प्लेमटफार्म से जुड़ चुके हैं, जिसमें 63.75 लाख किसानों ने ई-नाम पोर्टल पर अपनी फसलों का विक्रय कर लाभ प्राप्त किया है।

एसएफएसी अधिक से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों को ई-नाम योजना द्वारा लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। जिसके तहत लघु, मध्यम एवं सीमांत किसानों को ई-नाम द्वारा लाभ पहुंचाने जाने के लिए 16 राज्यों में 634 कृषक उत्पादक संगठनों का समावेश किया गया है। अभी तक इन कृषक उत्पादक संगठनों ने 549 मीट्रिक टन कृषि जिन्सों/उत्पादों का विक्रय किया है, जिसका मूल्य 1.89 करोड़ रुपए है। मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी लघु, मध्यम एवं सीमांत किसानों की आर्थिक संपन्नता में इजाफे के लिए प्रयासरत रहते हुए उनके कल्याण की दिशा में उदाहरण प्रस्तुत करेगी। ■

अप्रैल 2014 से 1.37 करोड़ ग्रामीण आवासों का हुआ निर्माण

केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सघन प्रयासों व राज्यों के सहयोग द्वारा अप्रैल 2014 से 1.37 करोड़ आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। आवासों के निर्माण कार्य पूरा होने का ब्यौरा निम्न है :

(संख्या लाख में)

वर्ष	ग्रामीण आवास पूरे हुए (आईएवाई+पीएमएवाई-जी)
2014-15	11.91
2015-16	18.22
2016-17	32.23
2017-18	44.54
2018-19 (अब तक)	30.45 (मार्च 31, 2019 तक 65 लाख होने की संभावना)
पूरे होने वाले आवासों की कुल संख्या	1.37 करोड़

गौरतलब है कि जहां 2014-15 में 12 लाख आवासों का निर्माण हुआ था, वहीं 2018-19 में यह संख्या पांच गुनी बढ़कर 65 लाख हो गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। राज्यों के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय को विश्वास है कि मार्च, 2019 तक एक करोड़ आवासों का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। पीएमएवाई-जी योजना के अंतर्गत निर्धनतम लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी कच्चे घरों में रहते हैं। 4.75 लाख घरों के निर्माण की मंजूरी लंबित है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीनों को जमीन देने का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे मामले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार से संबंधित है।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम से न सिर्फ गरीबों को आवास मिलता है, बल्कि उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 90/95 दिनों का रोजगार भी प्राप्त होता है। इन आवासों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं।

इन आवासों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया जाता है। 1.37 करोड़ ग्रामीण आवासों के लाभान्वितों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएमएवाई-जी योजना के तहत निर्धनतम लोगों के चयन के लिए त्रिस्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है– सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011, ग्राम सभा और ज्यो–टैगिंग। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)...............................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :................................... दिनांक :............................ बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 2019 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ व अन्य

केरल में एनएच 66 के कोल्लम बाईपास का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

लाल किला, नई दिल्ली में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम–1857 पर बने संग्रहालय को देखते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अहमदाबाद (गुजरात) में अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल–2019 के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19